घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 23, अंक - 23- गुरूवार 26- नवम्बर 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

कैबिनेट बैठक के फैसले...बांग्लादेश बॉर्डर से 20 किमी दूर असम में बनेगा एयरपोर्ट

कामराजर बंदरगाह पर दूसरे कंटेनर टर्मिनल के विकास को मंजूरी,4288 करोड़ रुपये होंगे खर्च

नई दिल्ली,25 नवम्बर 2026। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई। बैठक में पांच बड़े फैसले लिए गए। असम के सिलचर में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। इसके लिए सरकार ने 2014 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह एयरपोर्ट बांग्लादेश बॉर्डर से करीब 20 किमी दूर है।



पहला फैसला : भारत में ही बनेंगी बुलडोजर,क्रेन और सुरंग खोदने वाली मशीनें

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में सड़कें,पुल और सुरंगें बनाने का काम बढ़ने से बुलडोजर, क्रेन और बड़ी मशीनों की मांग बढ़ रही है। अभी भारत में इनकी आधी से ज्यादा जरूरत विदेशों से पूरी होती है। सरकार अब 11 हजार करोड़ रुपए खर्च कर अगले 8 साल में इन मशीनों और इनके पार्ट्स को देश में ही बनाने को बढ़ावा देगी। इसके लिए जेसीबी जैसी कंपनियों के साथ छोटे पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों को भी आर्थिक मदद मिलेगी। मशीनों की जांच के लिए अलग सेंटर बनाया जाएगा,जिसके लिए ARAI को 375 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वैष्णव के मुताबिक,सुरंग खोदने जैसी एक बड़ी मशीन बनाने में 500-600 कंपनियों के पार्ट्स लग सकते हैं।

दूसरा फैसला : कामराजर बंदरगाह पर दूसरे कंटेनर टर्मिनल के विकास को मंजूरी,4,288करोड़ रुपये होंगे खर्च

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चेन्नई के निकट स्थित कामराजर बंदरगाह (एन्नोर पोर्ट) पर दूसरे कंटेनर टर्मिनल के विकास को मंजूरी दे दी है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत डिजाइन,निर्माण,वित्त,संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर विकसित होने वाली इस परियोजना पर 4,288.26 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी। इस टर्मिनल की वार्षिक कंटेनर संचालन क्षमता 20 लाख टीईयू होगी। इसके लिए 900 मीटर लंबा बर्थ और 18 मीटर गहरा जलमार्ग विकसित किया जाएगा। परियोजना को दो चरणों में पूरा किया जाएगा और यहां 24,000 से अधिक टीईयू क्षमता वाले विशाल कंटेनर जहाजों को भी संभालने की सुविधा होगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि कामराजर बंदरगाह में कंटेनर टर्मिनल विकसित करने की व्यापक संभावनाएं हैं। इसकी विशेषता यह है कि बंदरगाह की आंतरिक परिवहन संपर्क व्यवस्था काफी अच्छी है और यहां तक रेलवे की सीधी कनेक्टिविटी भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि भारत में कंटेनर यातायात तेजी से बढ़ रहा है।

तीसरा फैसला : असम के सिलचर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी

केंद्र सरकार असम के सिलचर जिले के डोलू में 2,014 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास करेगी। एयरपोर्ट से पूर्वोत्तर भारत की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विकास गलियारों (ग्रोथ कॉरिडोर) के साथ कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय की योजना को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रमुख बुनियादी ढांचे के तौर पर 12,351 वर्ग मीटर की टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। व्यस्ततम समय में एयरपोर्ट की क्षमता 800 यात्रियों की होगी। इसमें 2,705 मीटर × 45 मीटर का रनवे होगा। साथ ही छह एयरबस ए-320 विमानों के लिए एप्रन पार्किंग क्षमता होगी। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट दक्षिण असम और बराक घाटी के लिए एक नया प्रवेश द्वार बनेगा। इससे मौजूदा सिलचर एयरपोर्ट की परिचालन और जगह संबंधी कमियों दूर होंगी। इससे दक्षिण असम और पड़ोसी राज्यों के नजदीकी इलाकों में हवाई यातायात की बढ़ती मांग पूरी होगी। इसके अलावा क्षेत्रीय व्यापार,पर्यटन और आर्थिक संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा।

चौथा फैसला : डाक संचालन योजना को 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने 25 नवंबर 2026 को डाक संचालन योजना को 16वें वित्त आयोग की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए 1,141 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है।

पांचवां फैसला : डाक विभाग के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 1,491 करोड़ मंजूर

केंद्रीय कैबिनेट ने 25 नवंबर 2026 को डाक विभाग की एस्टेट मैनेजमेंट स्कीम को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 1,491 करोड़ मंजूर किए हैं। इसके तहत देशभर में डाक विभाग के भवनों और सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा।

दीपम विवाद...तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी

कहा-मंदिर ट्रस्ट ने रोका,कोर्ट के आदेश के बावजूद स्तंभ पर नहीं जला दीप...



नई दिल्ली,25 नवम्बर 2026। तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने के विवाद को लेकर राज्य सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। मदुरै कलेक्टर ने कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बताया कि सरकार ने दीपथून यानी पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने की पूरी कोशिश की लेकिन देवस्थानम यानी मंदिर प्रशासन ने उसे रोका। सरकार के मुताबिक, मंदिर प्रशासन का कहना था कि दीपथून पर दीप जलाना स्थापित परंपराओं और धार्मिक रीति-रिवाजों के खिलाफ है। इसलिए दीप केवल उचि पिल्लैयार मंदिर के पास पारंपरिक स्थान पर जलाया गया। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि कार्तिक पूर्णिमा यानी 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाया जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया और जानबूझकर उसे टालने की कोशिश की। याचिकाकर्ता राम रविकुमार की ओर से पेश वकीलों ने अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे औपचारिक याचिका दाखिल करें, इसके बाद कोर्ट उचित आदेश देगा।

बीजेपी और हिंदू संगठनों के करीब 300 सदस्यों के खिलाफ केस

कार्तिगई दीपम विवाद के बीच बीजेपी और हिंदू संगठनों ने राज्य भर में प्रदर्शन किया। इस दौरान करीब 300 सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। रामनाथपुरम में हिंदू फ्रंट के सदस्यों ने सड़क जाम कर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने सड़क जाम करने वालों को हिरासत में लिया। पोल्लाची में हिंदू मुन्नानी के सदस्यों ने भी प्रदर्शन किया।

पहाड़ी पर लगातार दूसरे दिन आम लोगों की एंट्री बंद

विवाद के बाद बुधवार को लगातार दूसरे दिन श्रद्धालुओं और आम लोगों को तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर जाने से रोका गया। पलानी अंडावर मंदिर के प्रवेश द्वार के पास भारी पुलिस बल तैनात रहा। पहाड़ी की ओर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई। स्थानीय लोगों को भी जांच के बाद ही जाने दिया गया। पहाड़ी पर सुरक्षा व्यवस्था 23 नवंबर की शाम 6 बजे से लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति देते हुए आम लोगों, जुलूस और भीड़ को वहां जाने से रोकने का निर्देश दिया था। यह व्यवस्था कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई थी।

होम्योपैथी के क्षेत्र में मजबूत अनुसंधान संस्कृति विकसित करने के लिए संस्थान मिलकर करें काम : राष्ट्रपति मुर्मू

भुवनेश्वर,25 नवम्बर 2026। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुसंधान संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और पेशेवर संगठनों से होम्योपैथी के क्षेत्र में मजबूत अनुसंधान संस्कृति विकसित करने के लिए आपसी सहयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी की भविष्य की विश्वसनीयता और अकादमिक प्रतिष्ठा काफी हद तक उसके अनुसंधान की वैज्ञानिक सत्यनिष्ठा और उससे प्राप्त होने वाले नैदानिक साक्ष्यों की गुणवत्ता पर निर्भर करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय होम्योपैथी वैज्ञानिक सम्मेलन में शिरकत करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी भारत की विविध स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश की



स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुलभ, समतामूलक,वैज्ञानिक दृष्टि से जिम्मेदार और जनहित के प्रति संवेदनशील बनाने में संस्थानों, शोधकर्ताओं,शिक्षकों तथा स्वास्थ्य सेवा से जुड़े पेशेवरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सा से जुड़ा प्रत्येक निर्णय मरीज की गरिमा, सुरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा का अंतिम उद्देश्य लोगों की पीड़ा को कम करना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसलिए चिकित्सा के प्रत्येक क्षेत्र में मरीज का हित सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने होम्योपैथी के विकास में वैज्ञानिक अनुसंधान और गुणवत्तापूर्ण नैदानिक साक्ष्यों की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि होम्योपैथी की विश्वसनीयता और शैक्षणिक प्रतिष्ठा को मजबूत बनाने के लिए अनुसंधान में वैज्ञानिक ईमानदारी तथा प्रमाण आधारित दृष्टिकोण अनिवार्य है। उन्होंने अनुसंधान संस्थानों,मेडिकल कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और पेशेवर संगठनों से इस दिशा में मिलकर काम करने तथा अनुसंधान की मजबूत परंपरा विकसित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने कहा कि एक ऐसी स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था का निर्माण आवश्यक है,जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। इसके लिए चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े सभी पक्षों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संवेदनशीलता और मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए।

पासपोर्ट में जन्म स्थान पर सवाल उठने पर सौरभ दास से स्पष्टीकरण मांगा गया : विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली,25 नवम्बर 2026। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास के पासपोर्ट में दी गई जन्मस्थान की जानकारी को लेकर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने प्रश्न खड़ा किया था जिसके बाद उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। उनसे कहा गया है कि स्पष्टीकरण मिलने तक वे अपने पासपोर्ट का इस्तेमाल न करें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में एक प्रश्न पर कहा कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय अपेक्षा की जाती है कि आवेदक सही जानकारी दें। इसमें कमी या त्रुटि पाए जाने पर आवेदक को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है। चेन्नई के क्षेत्रीय कार्यालय से आधिकारिक जानकारी मिलने पर नोटिस दिया गया है। सौरभ दास को सात दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है और जवाब मिलने तक पासपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है।

उल्लेखनीय है कि सौरभ दास को दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन जाने से रोका गया था। उनके पासपोर्ट में जन्म स्थान को लेकर जांच जारी है। 23 नवंबर को देर रात एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की जांच के दौरान उनको रोका गया था। उनके खिलाफ नागरिकता और पासपोर्ट को लेकर एक मामला मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित है। सौरभ दास का कहना था कि वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में लेक्चर देने जा रहे थे।

विदेशी ताकतें भारत की तरक्की नहीं चाहतीं क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी : भागवत

छत्रपति संभाजी,25 नवम्बर 2026। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि दुनिया की कोई ताकत भारत की तरक्की नहीं चाहती। दुनिया की बड़ी शक्तियां अपना दबदबा कायम रखना चाहती हैं और दूसरों को दबाकर रखने की सोच में भरोसा करती हैं। भारत इसके विपरीत सभी की मदद करना चाहता है, यहां तक कि उन पड़ोसी देशों की भी जो उससे नफरत करते हैं। भागवत बुधवार को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पांचवें पद्मा फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम में पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान (रिटायर्ड) भी मौजूद थे।



अगर कोई ईमानदारी से बोलता है, तो युवा उसके साथ : भागवत ने युवाओं को लेकर कहा कि युवा झूठ से नफरत करते हैं और अपने देश को महान बनाना चाहते हैं। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि युवा पीढ़ी गुलामी के असर से मुक्त है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ईमानदारी से बोलता है, तो युवा उसके साथ खड़े होने को तैयार रहते हैं। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में युवाओं की भूमिका सबसे अहम होगी।

अमेरिकी टैरिफ...भारत समेत छह देशों से 25% शुल्क वसूलेगा अमेरिका,चीन पर 20% अतिरिक्त ड्यूटी लगेगी

नई दिल्ली,25 नवम्बर 2026। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के प्रशासन ने भारत सहित सात प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने का नया प्रस्ताव रखा है। यह कदम प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन की व्यापक अमेरिकी जांच के तहत उठाया गया है। वाशिंगटन का सीधा आरोप है कि ये देश बाजार मांग के विपरीत अत्यधिक विनिर्माण क्षमता और उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। इस नए ट्रेड आक्रामक रुख ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को एक बार फिर गहरे विनियामक दबाव में ला खड़ा किया है। अमेरिकी प्रशासन द्वारा घोषित प्रस्तावों के तहत भारत के अलावा छह अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर 25 प्रतिशत तक के अतिरिक्त शुल्क का शिकंजा कसा गया है।

इनमें शामिल देश हैं: भारत, दक्षिण कोरिया, ताइवान, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया।

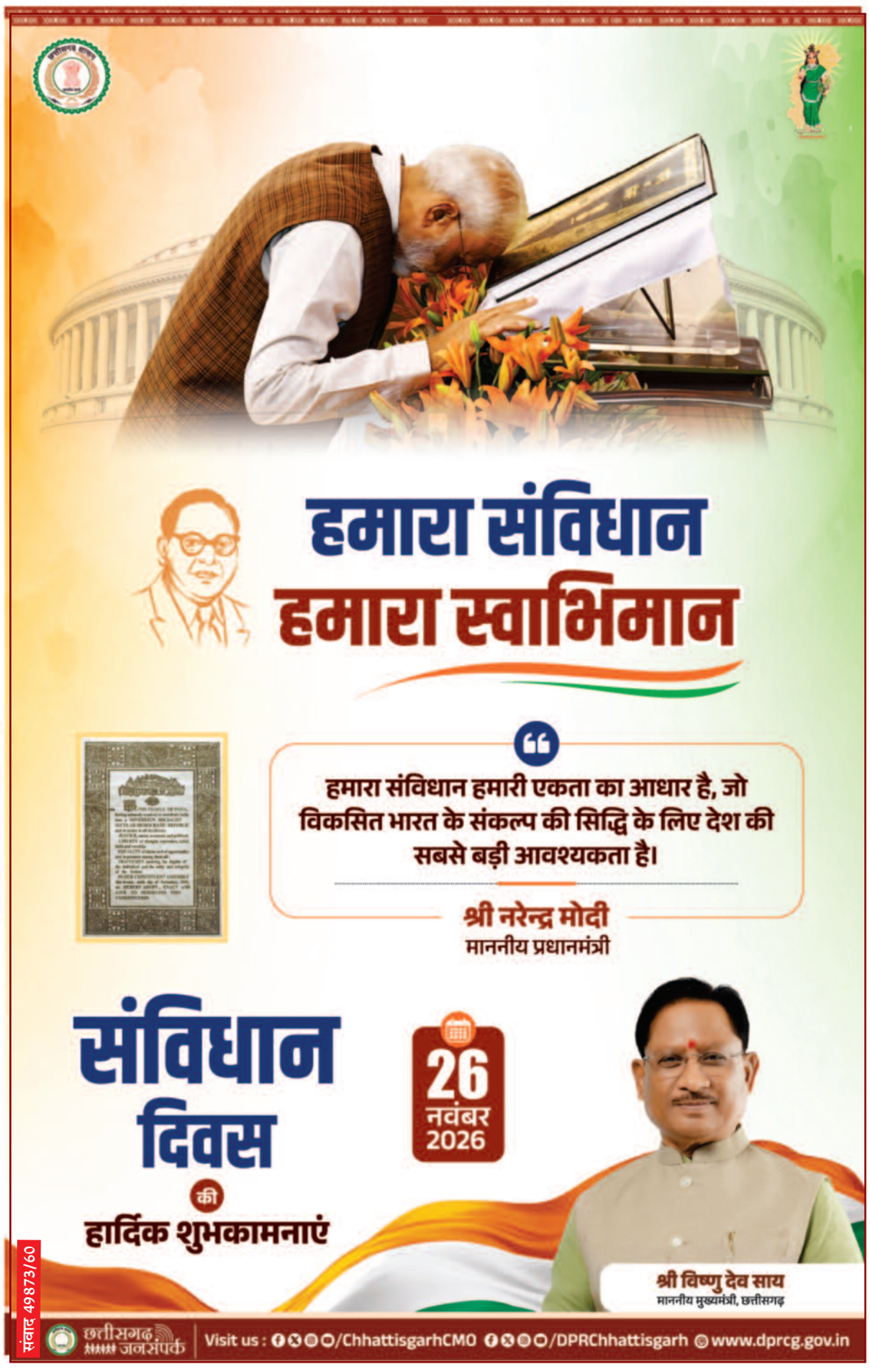

संपादकीय

विचार परिवर्तन के दौर में मुस्लिम समाज

बीते दिनों मुंबई में एक्स-मुस्लिम साहिल पर हमले की घटना चिंतनीय है। वर्तमान में तसलीमा नसरीन,आरिफ हुसैन तेरुवत, साहिल,जफर हेरेटिक और लियाकत अली जैसे एक्स-मुस्लिम अपनी पहचान बना चुके हैं। लियाकत एक्स मुस्लिम आफ केरल नामक संगठन के प्रमुख हैं। तमाम इस्लामी प्रचारक दुनिया भर में इस्लाम के बढ़ते जाने का दावा करते हैं,जबकि सच यह भी है कि मुस्लिम देशों में ही इस्लाम के प्रति उदासीनता बढ़ रही है,विशेषतः युवाओं में। इसे रोकने के लिए इस्लामी शासकों,संगठनों और इमामों के पास दंड,दबाव आदि के सिवा कुछ विशेष नहीं दिखता।

एक्स मुस्लिम साहिल पर हमला इसी का उदाहरण है। किसी व्यक्ति पर उसके विचारों के लिए हमला करना यही साबित करता है कि उसकी बात सच है,जिसका उत्तर देने में विफल होने के कारण उसे चुप कराने के लिए हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। इसीलिए साहिल पर हमले जैसी घटनाओं से युवाओं में इस्लामी मान्यताओं के प्रति संदेह ही बढ़ेगा। इसलिए भी कि तमाम इस्लामी देशों में पिछड़ेपन का ही आलम है। इसे मुस्लिम युवा कब तक नजरंदाज करेंगे! फलतः दुनिया में इस्लाम की बढ़त और घटत का दोहरा नजारा है।

एक ओर दुनिया भर में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और इसे प्यू रिसर्च का ताजा सर्वे भी बताता है, लेकिन दूसरी ओर इस्लाम छोड़ने और उससे उदासीन होने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यह क्रम लगातार बढ़ने से एक सीमा के बाद गुणात्मक परिवर्तन होना तय है। सभी प्रमुख मुस्लिम देशों में इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या बढ़ने पर है। कुछ वर्ष पहले पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआइए) ने इंटरनेट मीडिया पर चार लाख पाकिस्तानी अकाउंट से इस्लाम-विरोधी प्रचार होने का आंकड़ा दिया था। ईरान में कठोर इस्लामी शासन के बावजूद इस्लामी कायदों के विरुद्ध सार्वजनिक प्रतिवाद और प्रदर्शन की घटनाएं आए-दिन होती रहती हैं। यह संकेत है कि इस्लाम की वैचारिक ताकत पहले की तुलना में काफी कमजोर हो चुकी है। एक्स-मुस्लिमों की बढ़ती संख्या उसी का नतीजा है। चार दशक पहले कहा जाता था कि मुसलमानों में मजहब छोड़ने वाला नहीं होता,लेकिन अब कोई ऐसा नहीं कहता। पहले इस्लाम से दूर होने वाले मुस्लिम गोपन रहते थे। नाम बदल कर लिखा करते थे। अब अपने नाम,फोटो के साथ धड़ल्ले से नियमित और विस्तार से कट्टर इस्लामी मान्यताओं का खंडन करने वाले अनेक एक्स मुस्लिम डिजिटल मीडिया पर सक्रिय हैं।

घोर लापरवाही से हम सभी अकाल मृत्यु के मुंहाने पर

(विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस विशेष 26 नवंबर 2026)



डॉ0 प्रीतम गेडाम
महाराष्ट्र

पर्यावरण ही एकमेव जीवसृष्टि का आधार है, जबकि हर भारतीय दूषित हवा में सांस ले रहा, फिर भी हम नहीं सुधरते, पर्यावरण को सहेजना प्रत्येक की जिम्मेदारी हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए, हर साल 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता हैं। वाहनों से होने वाला उत्सर्जन और भीड़-भाड़,औद्योगिक गतिविधियां और थर्मल पावर,घरों में ठोस ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला जलाना,निर्माण कार्य और सड़कों की धूल,बायोमास और खुले में कचरा जलाना,खेतों में पराली जलाना,पटाखे जलाना,मौसम संबंधी कारणों से प्रदूषकों का जमा होना,बिना प्रक्रिया किया गया नगरपालिका का सीवेज,औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक वस्त्रोद्योग,अक्सर बिना उपचार किए भारी धातुओं और जहरीले कचरे को पास के जल स्त्रोतों में बहा देना,घातक रसायनों का प्रयोग होनेवाली खेती से बहकर आने वाला प्रदूषित पानी,ठोस और ई-अपशिष्ट का कुप्रबंधन,रासायनिक खादों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, खनन और औद्योगिक कचरे को कहीं भी फेंक देना,अनियंत्रित निर्माण कार्य और व्यावसायिक गतिविधियां। ऐसे अनेक कारण प्रदूषण स्तर को अत्यधिक खतरनाक मोड़ पर ले गये हैं।

पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 अनुसार,177 देशों की सूची में भारत को 22.46 के स्कोर के साथ 176वां स्थान मिला है,इस स्थान से हम गंभीर वास्तविकता का अंदाजा लगा सकते है, भारत देश 2016 में 141वें स्थान पर था। 2022 से भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले पांच देशों में शामिल रहा है। हमारा स्कोर भूटान 82वें, श्रीलंका 118वें,नेपाल 134वें, पाकिस्तान 148वें और बांग्लादेश 161वें जैसे पड़ोसी देशों की तुलना में पिछड़ा हुआ हैं। लगातार बढ़ रहे शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण वायु गुणवत्ता,जैव विविधता और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर लगातार दबाव बना हैं। हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन,स्वच्छता के बुनियादी सुविधा ने सकारात्मक सहयोग दिया हैं। जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122 देशों में से 120वें स्थान पर हैं। 2026 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 122 देशों में से भारत 100वें स्थान पर है। इसका स्कोर 24.1 है, जो इसे गंभीर भुखमरी की श्रेणी में रखता हैं। वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक अनुसार, भारत देश दुनिया का दूसरा सबसे अधिक प्रदूषित देश है। भारत देश की लगभग 140 करोड़ जनता ऐसे वातावरण में रहती है, जहां की वायु विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दर्शाये पीएम2.5 से भी अधिक हैं। कुछ हिस्से में तो यह भारत के अपने राष्ट्रीय मानक से भी कहीं ज्यादा ऊपर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बताये गए दिशानिर्देशों अनुसार,सूक्ष्म कण एक औसत भारतीय की जीवन प्रत्याशा को लगभग 3.5 साल कम कर देते है, जबकि दिल्ली-एनसीआर जैसे स्थल के निवासियों की जीवन प्रत्याशा में 8.2 साल तक की कमी आ सकती हैं।

स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 की रिपोर्ट बताती है कि,2023 में भारत में 20 लाख से अधिक मौतें वायु प्रदूषण के कारण हुई, जो 2000 के मुकाबले 43 फीसदी ज्यादा है और द लैंसेट काउंटडाउन 2025 के मुताबिक,2022 में 17.2 लाख मौतें केवल इंसानों द्वारा निर्मित सूक्ष्म कणों की वजह से हुई, इस नुकसान की कीमत 339.4 अरब अमेरिकी डॉलर आंकी गई है,जो भारत की जीडीपी का 9.5 प्रतिशत है। इन आंकड़ों से ही आकलन लगा सकते हैं कि,देश में प्रकृति के प्रति घोर लापरवाही और पर्यावरणीय ह्रास की कितनी बड़ी कीमत आम इंसान को चुकानी पड़ रही हैं। प्रदूषण के कारण जानलेवा बीमारियां जैसे हृदय संबंधी बीमारियां,स्ट्रोक, फेफड़ों को लगातार नुकसान पहुंचना और सांस लेने में गंभीर संकट,निमोनिया और श्वसन संबंधी संक्रमण,कैंसर पैदा करने वाले प्रदूषकों और औद्योगिक उत्सर्जन के लंबे समय तक सांस के जरिए शरीर में जाने से होने वाले कैंसर, मेटाबॉलिक,किडनी और पानी से होने वाली बीमारियां,टाइप 2 डायबिटीज, दीर्घकालिक वृक्क रोग का खतरा लगातार बढ़ता हैं। यह बीमारियां बेहद खर्चीली एवं मौत के मुंह में धकेलनेवाली हैं। अभी हाल ही में इंडिया टुडे में प्रकाशित एक खबर पढ़ी, जिसमें मशहूर चिकित्सक डॉ. संजीव बागई ने,देश में वायु प्रदूषण से हर साल होनेवाली मौतों की तुलना हिरोशिमा, नागासाकी और कोविड-19 से होने वाली मौतों से की। प्रदूषण मनुष्य के प्रत्येक अंग को नुकसान पहुंचा रहा है,यहा तक की गर्भवती महिला के पेट में पल रहे बच्चे को भी बीमार कर रहा हैं।



प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

हर चीज प्रकृति की देन है, हर व्यवसाय या उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल भी पर्यावरण से ही मिलता हैं। पिछले कुछ दशकों में मानव ने विकास के नाम पर खूब यांत्रिकी संसाधनों की खोज की और मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जमकर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया हैं। बहुत-सी प्राकृतिक चीजे तो आनेवाली पीढ़ियों को दिखेगी भी नहीं, अर्थात उनके हिस्से की भी चीजे आज मानव उपभोग चूका हैं। अक्सर कोयला और खनिजों के खनन के लिए या औद्योगिक आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए जंगल काटते है,राजमार्ग,रेलवे लाइन, बांध बनाने या शहरीकरण के लिए जमीन साफ करते हैं। फर्नीचर,कागज, निर्माण कार्य के लिए लकड़ी और ईंधन के लिए भी लगातार पेड़ कटते हैं। लेकिन जंगलों को खत्म करने से वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट होते हैं। उपजाऊ मिट्टी का क्षरण होता है,मिट्टी का कटाव होता है,जिसके कारण बाढ़ या सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है,शुद्ध प्राणवायु कम होती हैं। प्रदूषण बढ़ता है,प्राकृतिक आपदायें लगातार बढ़ती हैं। इसका सीधा असर जीवसृष्टि के प्रत्येक जीव,पर्यावरण के हर घटक,ऋतुचक्र और जलवायु पर पड़ता हैं। हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर होती है,बीमारियां बढ़ती है,अकाल मृत्यु में भयावह वृद्धि होती हैं।

पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण के कारण एवं उसके रोकथाम के उपाय सबको पता है, अर्थात सरकार से लेकर एक सामान्य नागरिक तक इस बारे में जानते है। शुद्ध जल,स्वच्छ ऑक्सीजन और पर्याप्त पोषक आहार हर मनुष्य का अधिकार और जरुरत हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति सबकी जवाबदेही है,प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है,कि वो पर्यावरण बचायें। पर्यावरण के बारे में लोग गंभीरता से नहीं सोचते और सरकारी नियमों एवं कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाते है,जो कि अब हम सबके जान पर बन आयी हैं। पर्यावरण की रक्षा और प्रदूषण कम करने के लिए अमीर-गरीब,शिक्षित-अशिक्षित,नेता-जनता, अधिकारी, उद्योगपति सभी ने सरकारी निति-नियमों का कड़ाई से पालन एवं प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता रखनी होगी,भ्रष्टाचार का कोई नामोनिशान नहीं होना चाहिए। मनुष्य से ज्यादा जीवजंतु,पशु-पक्षी,प्राणी इस पर्यावरण की रक्षा करते हैं। क्या मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना अँधा हो गया है कि,जानवरों को पर्यावरण के रक्षा की समझ है,लेकिन मनुष्य को नहीं,क्या मनुष्य जानवरों से भी निचे के स्तर पर गिर चूका हैं।

पंजाब में भाजपा-अकाली गठबंधनः सत्ता परिवर्तन की नई आहट



ललित गर्ग
पटपड़गंज,दिल्ली

पंजाब की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का छह वर्ष बाद फिर साथ आना केवल दो राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन की वापसी नहीं है,बल्कि यह पंजाब के बदलते राजनीतिक समीकरणों की महत्वपूर्ण आहट है,इससे आम आदमी पार्टी का संकट बढ़ेगा और पंजाब के राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। गुरुनानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर घोषित यह गठबंधन 2027 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार के सामने एक मजबूत चुनौती के रूप में उभर सकता है। दोनों दलों का पुराना राजनीतिक रिश्ता,साझा शासन का अनुभव और एक-दूसरे के पूरक सामाजिक आधार इस गठबंधन को विशेष महत्व देते हैं। हालांकि चुनावी राजनीति में किसी गठबंधन की घोषणा सत्ता परिवर्तन की गारंटी नहीं होती, लेकिन इतना निश्चित है कि पंजाब में अब मुकाबला पहले की तुलना में अधिक रोचक,प्रतिस्पर्धी और त्रिकोणीय हो गया है। भाजपा और अकाली दल का संबंध राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के औपचारिक गठन से भी पुराना है। अटल बिहारी वाजपेयी,लालकृष्ण आडवाणी और प्रकाश सिंह बादल के दौर में दोनों दलों ने जिस राजनीतिक साझेदारी की नींव रखी थी,वह लंबे समय तक पंजाब की राजनीति में सफल मॉडल बनी रही। अकाली दल का ग्रामीण और सिख समाज में प्रभाव तथा भाजपा का शहरी हिंदू,व्यापारी और मध्यवर्गीय आधार एक-दूसरे के पूरक रहे। इसी सामाजिक और राजनीतिक समीकरण के कारण दोनों दलों ने मिलकर पंजाब में कई बार सत्ता हासिल की। लेकिन 2020 में तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों के व्यापक आंदोलन के बीच यह रिश्ता टूट गया। अकाली दल ने भाजपा से दूरी बनाई और हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उस समय यह निर्णय किसानों की भावनाओं और पंजाब की राजनीतिक परिस्थितियों के दबाव में लिया गया था, लेकिन बाद के चुनावों ने यह भी दिखाया कि इस अलगाव की राजनीतिक कीमत दोनों दलों को चुकानी पड़ी।

2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर पंजाब की सत्ता पर शानदार ढंग से कब्जा किया। दूसरी ओर अकाली दल तीन और भाजपा केवल दो सीटों तक सिमट गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों दल अलग-अलग मैदान में उतरे। कांग्रेस ने सात,आम आदमी पार्टी ने तीन और अकाली दल ने एक सीट जीती, जबकि भाजपा एक भी सीट नहीं जीत सकी। हालांकि भाजपा का मत प्रतिशत करीब 18.6 प्रतिशत रहा और अकाली दल को भी लगभग 13.5 प्रतिशत वोट मिले। इससे स्पष्ट हुआ कि दोनों दलों के पास अलग-अलग पर्याप्त राजनीतिक आधार है,लेकिन अलग-अलग लड़ने पर वह वोट प्रभावी सीटों में परिवर्तित नहीं हो पा रहा है। अब छह वर्ष बाद दोनों दलों ने अपने अनुभवों से सबक लेते हुए फिर साथ आने का फैसला किया है। इसे राजनीतिक भूल-सुधार भी कहा जा सकता है और बदली परिस्थितियों की व्यावहारिक स्वीकृति भी। इस गठबंधन का सबसे बड़ा प्रभाव आम आदमी पार्टी पर पड़ना स्वाभाविक है। 2022 में आप को सबसे बड़ा लाभ विपक्ष के बिखरे होने से मिला था। कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा अलग-अलग चुनाव लड़ रहे थे और सत्ता विरोधी मत एकजुट विकल्प में परिवर्तित नहीं हो पाए। अब भाजपा और अकाली दल के साथ आने से यह समीकरण बदल गया है। भाजपा का शहरी और मध्यवर्गीय आधार तथा अकाली दल का ग्रामीण संगठन और पारंपरिक जनसंपर्क यदि प्रभावी ढंग से एक-दूसरे के पक्ष में वोट ट्रांसफर कर पाते हैं,तो आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित रूप से चुनौती बढ़ेगी। यही कारण है कि इस गठबंधन को पंजाब की वर्तमान सरकार के लिए गंभीर राजनीतिक खतरे की शुरुआत माना जा सकता है।



भाजपा के लिए भी यह गठबंधन रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पंजाब में उसने अपना मत प्रतिशत बढ़ाया है, लेकिन उसे सीटों में बदलने में कठिनाई रही है। अकेले चुनाव लड़कर व्यापक ग्रामीण और सिख सामाजिक आधार तक पहुंच बनाना उसके लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। अकाली दल के साथ आने से उसे पंजाब की स्थानीय सामाजिक संरचना में अधिक व्यापक पहुंच मिल सकती है। दूसरी ओर अकाली दल के लिए यह गठबंधन राजनीतिक पुनर्जीवन का अवसर है। कभी पंजाब की राजनीति की निर्णायक शक्ति रहे अकाली दल का जनाधार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से कमजोर हुआ है। भाजपा के साथ लौटना उसके लिए केवल सत्ता में वापसी की कोशिश नहीं,बल्कि संगठन और कार्यकर्ताओं में नया विश्वास पैदा करने का अवसर भी है। फिर भी इस गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती विश्वसनीयता की है। छह वर्ष पहले जिस कृषि कानून मुद्दे पर दोनों दल अलग हुए थे, अब उसी रिश्ते को पुनर्जीवित करने पर स्वाभाविक सवाल उठेंगे। अकाली दल को अपने मतदाताओं को समझाना होगा कि परिस्थितियां क्यों बदलीं और आज भाजपा के साथ आने का आधार क्या है। भाजपा को भी किसानों के साथ संवाद की नई और भरोसेमंद भाषा विकसित करनी होगी। लोकतंत्र में गठबंधन बनाना राजनीतिक दलों का अधिकार है,लेकिन जनता के विश्वास का सम्मान करना उनकी जिम्मेदारी भी है। विचारधारात्मक मतभेदों के बावजूद साथ आना अपने आप में अवसरवाद नहीं है,समस्या तब होती है जब राजनीतिक दल अपने पुराने रुख और वर्तमान निर्णय के बीच कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं दे पाते।

पश्चिम बंगाल और दिल्ली के राजनीतिक अनुभवों की पृष्ठभूमि में पंजाब का घटनाक्रम भाजपा की रणनीति को समझने का एक अवसर देता है। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने लंबे समय से मजबूत राजनीतिक आधार रखने वाली शक्तियों के बीच अपनी जगह बनाई और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मजबूत सत्ता को चुनौती देकर सत्ता हासिल की। पंजाब में परिस्थितियां अलग हैं,लेकिन भाजपा अब यहां भी संगठन,गठबंधन और सामाजिक समीकरणों के माध्यम से सत्ता की संभावना तलाश रही है। अकाली दल का साथ इस रणनीति को स्थानीय आधार दे सकता है। लेकिन पंजाब की जनता केवल राजनीतिक गणित से प्रभावित नहीं होगी। किसान,युवा, रोजगार, नशा, उद्योग,कानून-व्यवस्था,शिक्षा और राज्य की आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दे चुनाव का वास्तविक आधार बनेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा-अकाली गठबंधन को कागज पर वोट जोड़ने से आगे बढ़कर जमीन पर कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को जोड़ना होगा। छह वर्ष तक अलग रहने के बाद दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच पैदा हुई दूरी को समाप्त करना आसान नहीं होगा। नेतृत्व का समझौता हो जाना पर्याप्त नहीं है,बूथ स्तर तक राजनीतिक सहयोग और आपसी विश्वास जरूरी होगा। यदि भाजपा कार्यकर्ता अकाली उम्मीदवार के लिए और अकाली कार्यकर्ता भाजपा उम्मीदवार के लिए पूरी निष्ठा से काम करते हैं,तभी गठबंधन की वास्तविक शक्ति सामने आएगी।

पंजाब में अब चुनावी मुकाबला केवल सरकार बनाम विपक्ष नहीं रह गया है। यह आम आदमी पार्टी के शासन के मूल्यांकन,कांग्रेस की वापसी की कोशिश और भाजपा-अकाली गठबंधन की नई राजनीतिक संभावनाओं के बीच त्रिकोणात्मक मुकाबला होगा। भाजपा-अकाली गठबंधन निश्चित रूप से आप के लिए खतरे की घंटी है,लेकिन इसे सत्ता परिवर्तन की गारंटी मानना भी उचित नहीं होगा। अंततः चुनावी निर्णय जनता के प्रदर्शन और विश्वास पर निर्भर करेगा। यदि आप सरकार जनता के बीच अपना भरोसा बनाए रखती है तो गठबंधन की चुनौती सीमित रह सकती है,लेकिन यदि सत्ता विरोधी भावना मजबूत हुई तो भाजपा-अकाली गठबंधन उस भावना को एक संगठित राजनीतिक विकल्प दे सकता है। इस गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि क्या भाजपा और अकाली दल केवल सत्ता पाने के लिए फिर साथ आए हैं या पंजाब के लिए कोई साझा भविष्य-दृष्टि भी रखते हैं। यदि वे किसानों के सम्मान, युवाओं के रोजगार, नशामुक्त पंजाब, उद्योग के विकास, कानून-व्यवस्था और हिंदू-सिख भाईचारे को अपने साझा एजेंडे का केंद्र बनाते हैं तो यह गठबंधन केवल चुनावी समझौता नहीं,पंजाब की राजनीति में नई धुरी बन सकता है। 2020 का अलगाव,2022 की हार और 2024 का अलग-अलग चुनाव दोनों दलों को यह सिखा चुका है कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं,लेकिन साझा राजनीतिक जमीन को पूरी तरह खो देना किसी के हित में नहीं। अब 2027 बताएगा कि यह पुनर्मिलन केवल सत्ता की मजबूरी है या वास्तव में पंजाब की राजनीति में एक नई शुरुआत एवं शुभ भविष्य की आहट है। गठबंधन का हाथ नेताओं ने मिलाया है,लेकिन उसकी सफलता का फैसला पंजाब की जनता करेगी।

भाजपा को सत्ता से हटाने चले,सीटों पर ही उलझे विपक्षी दल

2027 की लड़ाई से पहले विपक्ष दिल्ली की बैठकों में उलझा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भाजपा को हराने का दावा करती हैं, पर उनकी बातचीत का केंद्र जनता,बेरोजगारी या महंगाई नहीं, सीटों की गिनती और राजनीतिक हैसियत बन गई है। जिस गठबंधन को भाजपा के लिए चुनौती बनना था, वह अभी अपने भीतर भरोसा कायम नहीं कर पा रहा। यह कमजोरी भाजपा के लिए अवसर है। सपा ने कांग्रेस के सामने 26 सीटों का प्रस्ताव रखा है। कांग्रेस की ओर से पहले 181 सीटों की मांग की खबर आई,फिर 130 और 120 सीटों के आसपास की दावेदारी सामने आई। फासला साफ है। अखिलेश का तर्क है कि सीटें जीतने की संभावना के आधार पर मिलनी चाहिए। पर जीत का पैमाना कौन तय करेगा? क्या सपा अपने उम्मीदवारों को भी इसी कसौटी पर परखेगी? कांग्रेस की हालत भी किसी भ्रम में रहने लायक नहीं। 2022 में उसने 399 सीटों पर चुनाव लड़ा, सिर्फ दो जीतीं,उसका वोट प्रतिशत 2.33 रहा और 387 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। ऐसे प्रदर्शन के बाद 120-130 सीटों का दावा आत्ममुग्धता लगता है। मगर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश की 17 में से छह सीटें जीतीं और 9.46 प्रतिशत वोट पाए। सपा ने 62 में से 37 सीटें जीतकर 33.60 प्रतिशत मत हासिल किए। लोकसभा नतीजे विधानसभा की गारंटी नहीं,लेकिन कांग्रेस शून्य भी नहीं। दोनों दल अपने अनुकूल आंकड़े चुन रहे हैं। सपा की 26 सीटों वाली सूची में रामपुर खास और फरेंदा जैसी कांग्रेस की जीती सीटें हैं। मथुरा, खेरागढ़,जगदीशपुर और किदवई नगर वे क्षेत्र हैं जहां कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी। बागपत, मोदीनगर,हापुड़, जेवर,स्याना,खुर्जा, खैर, इगलास,मांट,आगरा उत्तर, फतेहपुर सीकरी, बिलग्राम-मल्लावां, गोविंद नगर,नानपारा,गोरखपुर शहर, खजनी,पडरौना,फाजिलनगर,पिंडरा और वाराणसी कैंट भी प्रस्ताव में बताए गए हैं। कई क्षेत्रों में कांग्रेस के हजार-दो हजार वोट सपा के तर्क को बल देते हैं,पर जीत उम्मीदवार, समीकरण,संगठन और वोट हस्तांतरण से तय होगी।



अजय कुमार
लखनऊ (उ.प्र.)

अखिलेश की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल यह हो सकती है कि वह गठबंधन को साझेदारी नहीं,अधीनता समझ बैठें। पांच प्रत्याशियों की घोषणा बेहट से उमर अली खान,सहारनपुर से आशु मलिक,कैराना से नाहिद हसन, अमरोहा से महबूब अली और ललितपुर से ज्योति लोधी सीटों पर बातचीत के बीच हुई। यह संगठन की तैयारी हो सकती है, लेकिन सहयोगी को भरोसे में लिए बिना घोषणा दबाव की राजनीति लगती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के दावों के बीच यह कदम और चुभता है। इमरान मसूद का आक्रोश इसी अपमानबोध से निकला है। उनका कहना है कि कांग्रेस भीख नहीं मांग रही और गठबंधन में सीटें दया से नहीं, आपसी सहयोग से तय होती हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस ने सीटें मांगी ही नहीं तो 26 का आंकड़ा थोपने का अधिकार किसने दिया। सपा को समझना होगा कि सहयोगी को सार्वजनिक रूप से छोटा करने की कीमत चुकानी पड़ती है। कांग्रेस भी बताए कि कमजोर संगठन वाली सीटों पर उसका दावा किस आधार पर है। ओमप्रकाश राजभर ने इमरान के बयान पर तंज कसते हुए पूछा कि यदि कांग्रेस भीख नहीं मांग रही तो सीटों पर बातचीत के लिए कमेटी लेकर सपा के पास क्यों गई। सपा सांसद एसपी सिंह पटेल ने भी कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसे 50 सीटें देना भी बड़ी बात होगी। उन्होंने कांग्रेस के संगठन और उम्मीदवारों की क्षमता पर भी सवाल उठाए। ऐसे बयान बताते हैं कि भाजपा से मुकाबले की तैयारी कर रहे दोनों दलों के बीच भरोसे से ज्यादा एक-दूसरे की हैसियत नापने की होड़ लगी है। पांच नामों की सामाजिक बनावट भी संदेश देती है। चार मुस्लिम चेहरे और एक ओबीसी महिला उम्मीदवार के जरिए सपा मुस्लिम प्रतिनिधित्व और पिछड़े वर्ग की भागीदारी का दावा मजबूत करना चाहती है। पीडीए पिछड़ा,दलित और अल्पसंख्यक तभी चलेगा जब गैर-यादव पिछड़ों और दलितों को टिकट,संगठन और सत्ता में हिस्सेदारी मिले। मुस्लिम मतदाता भी सुरक्षा,शिक्षा,रोजगार और सम्मान चाहते हैं। ओवैसी की राजनीति मुस्लिम मतों में विकल्प का सवाल उठाती है, जबकि बसपा दलित मतों पर अपनी पकड़ लौटाने की कोशिश कर सकती है। सपा का गणित इन दोनों चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। 26 नवंबर को संविधान दिवस पर प्रस्तावित पीडीए प्रणपत्र सपा की दूसरी बड़ी परीक्षा है। प्रदेश,75 जिलों और लखनऊ के लिए अलग दस्तावेज बनाने की तैयारी स्थानीय मुद्दों को जगह देने का अवसर है।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य में असफल

आज का वैश्विक परिदृश्य एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है, जहाँ कूटनीति की भाषा लगातार कमजोर पड़ती जा रही है और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख माध्यम बनता जा रहा है। पश्चिम एशिया में अमेरिका,इज़रायल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया है,बल्कि उसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। हाल के दिनों में युद्धविराम और शांति वार्ताओं की चर्चाओं के बीच एक बार फिर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और उसके जवाब में ईरान की प्रतिक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्थिति अभी भी अत्यंत नाजुक बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी स्थापना के मूल उद्देश्य से सर्वथा असफल रहा है कुछ बाहुबली देशों की संयुक्त राष्ट्र कठपुतली बनकर रह गया है, इन परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का पुनर्गठन आवश्यक हो गया है। अंतरराष्ट्रीय समाचारों के अनुसार हालिया संघर्ष में अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं और अमेरिकी नेतृत्व ने युद्धविराम व्यवस्था के प्रभावी न रहने की बात कही है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इतिहास बताता है कि शांति वार्ताएँ तभी सफल होती हैं जब सभी पक्ष समझौते के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता रखें। यदि वार्ताओं के समानांतर सैन्य तैयारियाँ और शक्ति प्रदर्शन जारी रहें, तो स्वाभाविक रूप से अविश्वास बढ़ता है। यही कारण है कि आज अनेक रणनीतिक विश्लेषक यह प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या वर्तमान वार्ताएँ स्थायी शांति की दिशा में बढ़ रही हैं या केवल समय प्राप्त करने का माध्यम बन रही हैं। यह एक दृष्टिकोण है, किंतु इसका अंतिम निष्कर्ष भविष्य की घटनाएँ ही तय करेंगी।अमेरिका का तर्क रहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियाँ उसके सहयोगियों तथा अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के लिए चुनौती हैं। दूसरी ओर ईरान लगातार यह कहता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और उसकी संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए। इज़रायल लंबे समय से ईरान को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानता है। इन परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों ने विश्वास का ऐसा संकट पैदा कर दिया है, जिसने समाधान की राह को अत्यंत कठिन बना दिया है।



संजीव ठाकुर
रायपुर,छ0ग0

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों ने भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने संकेत दिया है कि यदि अमेरिकी हितों या अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर खतरा बना रहा तो आगे भी सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र तथा अनेक देशों ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और संवाद के माध्यम से समाधान खोजने की अपील की है। यदि यह संघर्ष और व्यापक होता है तो उसका सबसे पहला प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पश्चिम एशिया विश्व के ऊर्जा संसाधनों का प्रमुख केंद्र है। होरमुज़ जलडमरूमध्य से होकर विश्व के बड़े हिस्से का तेल परिवहन होता है। यदि वहाँ अस्थिरता बढ़ती है तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि होना स्वाभाविक है। इसका सीधा असर भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों पर पड़ेगा। पेट्रोल,डीज़ल,रसोई गैस,परिवहन,खाद्य पदार्थ और औद्योगिक उत्पादन सभी महँगे हो सकते हैं। महँगाई बढ़ने से सबसे अधिक कठिनाई निम्न एवं मध्यम वर्ग को होगी।

आर्थिक संकट के साथ-साथ मानवीय संकट भी गहरा सकता है। युद्ध

संतान और बीमारी ठीक करने का झांसा देकर लाखों की ठगी,कथित बाबा गिरफ्तार

रसूलपुर के 'बाबे शिफा' में चला रहा था कथित ठगी का धंधा, बैकुंठपुर के व्यक्ति से 9 लाख तो अन्य लोगों से भी ऐंठे लाखों रुपए

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

संतान देने,बीमारी ठीक करने और जादू-टोने का असर खत्म करने का दावा कर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले कथित बाबा को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर निवासी नौशाद अली शहर के रसूलपुर में 'बाबे शिफा' के नाम से अपनी गतिविधियां चला रहा था। वह खुद को रुहानी ताकतों का मालिक और खुदा का मसीहा बताकर लोगों को झांसे में लेता था। अब तक करीब 40 लाख रुपए की ठगी का दावा सामने आया है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोमिनपुरा निवासी यासिर अंसारी ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी अग्रसेन चौक के पास जूते-चप्पल की दुकान



है। उसे जानकारी मिली थी कि रसूलपुर निवासी दीपक खान के घर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर निवासी नौशाद अली सूफी सईद बाबा के नाम से लोगों का इलाज और जादू-टोने से समस्याएं दूर करने का दावा कर रहा है। इस जगह को 'बाबे शिफा' नाम दिया गया था। आरोपी ने यासिर को भी झांसे में लेकर उससे 75 हजार रुपए ले लिए। वह निःसंतान दंपतियों को संतान देने का भी दावा करता था। शिकायत के अनुसार, उसने मोमिनपुरा के कई लोगों सहित बैकुंठपुर निवासी एक व्यक्ति से भी लाखों रुपए ऐंठे हैं।

किसी से 9 लाख तो किसी से 4 लाख रुपए लिए...

पीड़ितों के अनुसार, आरोपी ने बैकुंठपुर निवासी बाबा खान से करीब 9 लाख रुपए, रसूलपुर निवासी शाहिद से 4 लाख रुपए, आदिल से 10 हजार, शोएब अख्तर से 20 हजार, समीर सिद्दीकी से 20 हजार और लारेब अहमद से 20 हजार रुपए लिए हैं। यासिर अंसारी से भी 75 हजार रुपए ऐंठे गए। लोगों ने आरोपी को फोन-पे सहित अन्य ऑनलाइन माध्यमों से रकम भेजी थी। पीड़ितों ने भुगतान के स्क्रीनशॉट भी पुलिस को सौंपे हैं।

गिरफ्तारी की मांग को लेकर कोतवाली पहुंचे पीड़ित...

मंगलवार रात ठगी के शिकार लोग शिकायत लेकर कोतवाली पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने आरोपी के निवास स्थल का घेराव भी किया। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने नौशाद अली पिता निसार अली को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 18(4) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बेटे की मौत पर संदेह, परिजन पहुंचे आईजी के पास

शिवम के बदलते बयानों पर उठाए सवाल,अक्टूबर में बाईपास पर मिला था युवक का शव...एएसपी स्तर के अधिकारी करेंगे दोबारा जांच

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले में अक्टूबर माह में हुई एक युवक की मौत का मामला अब सरगुजा रेंज के आईजी कार्यालय पहुंच गया है। मृतक के परिजनों ने पुलिस की अब तक की जांच पर सवाल उठाते हुए मामले की दोबारा निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। परिजनों को आशंका है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। उनका आरोप है कि पुलिस ने संदेह के बिंदुओं की गंभीरता से जांच नहीं की। कोरिया जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तरगवां निवासी मृतक के भाई बृजेश कुमार साहू और कमला बाई ने आईजी को सौंपे आवेदन में बताया कि 18 अक्टूबर को उनके भाई को पड़ोस में रहने वाला शिवम नामक युवक करमा देखने के बहाने घर से ले गया था। इसके बाद दोपहर 3.17 बजे परिजनों को फोन आया कि बाईपास पर दुर्घटना में युवक घायल होकर बेहोश हो गया है। परिजन मौके पर पहुंचे तो युवक मृत अवस्था में मिला।

परिजनों का आरोप है कि घटना के संबंध में पूछताछ के दौरान शिवम बार-बार अपने बयान बदलता रहा। कभी उसने बोलेरो वाहन में आने की बात कही तो कभी तीन लोगों द्वारा मारपीट किए जाने की जानकारी दी। बयानों में विरोधाभास के बावजूद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच नहीं की। परिजनों का कहना है कि वे मामले में कार्रवाई



के लिए स्थानीय पुलिस अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। थक-हारकर वे अंबिकापुर स्थित आईजी कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की नए सिरे से जांच की मांग की। उनकी मांग है कि शिवम के बयानों की पड़ताल के साथ घटना के दिन की कॉल डिटेल,घटनास्थल और बाईपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर वास्तविकता सामने लाई जाए।

एएसपी स्तर के अधिकारी करेंगे जांच : सरगुजा रेंज के आईजी दीपक कुमार झा ने बताया कि कोरिया जिले में अक्टूबर माह में एक युवक की मौत हुई थी। परिजनों को आशंका है कि उसकी हत्या की गई है। उन्होंने पुलिस जांच में कुछ खामियां होने की बात कहते हुए लिखित शिकायत दी है। आईजी ने परिजनों की मौजूदगी में ही कोरिया एसपी और थाना प्रभारी से चर्चा की तथा शिकायत में उठाए गए सभी बिंदुओं की जांच के निर्देश दिए हैं। अब मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी करेंगे।

तीन घरों से 16 बकरा-बकरी चोरी,दो थाना क्षेत्रों में वारदात

लखनपुर में दो घरों को बनाया निशाना,प्रतापपुर के केरता गांव में भी चोरी...पुलिस ने दर्ज किया मामला

-संवाददाता-
लखनपुर/प्रतापपुर,25 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा और सूरजपुर जिले के दो थाना क्षेत्रों में चोरों ने तीन घरों से 16 बकरा-बकरी पार कर दिए। लखनपुर थाना क्षेत्र में 20 नवंबर की रात दो घरों में चोरी हुई, जबकि प्रतापपुर थाना क्षेत्र के केरता गांव में 22 नवंबर की रात चोरों ने दो घरों को निशाना बनाया। चोरी गए मवेशियों की कुल कीमत करीब 92 हजार रुपए बताई गई है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लखनपुर थाना क्षेत्र के दिपनारायण राजवाड़े ने पुलिस को बताया कि 20 नवंबर की रात उन्होंने पांच बकरा-बकरी कमरे में बांधकर ताला लगा दिया था। 21 नवंबर की सुबह उठे तो कमरे का ताला टूटा मिला और सभी पांच मवेशी गायब थे। इनमें दो बकरी, दो बकरा और एक खस्सी शामिल थी। इनकी कीमत करीब 25 हजार रुपए बताई गई है। इसी रात दूसरी वारदात में रमेश्वरी बाई के घर से चार बकरियां चोरी हो गईं। महिला के अनुसार,रात करीब 3 बजे दरवाजा खुलने की आहट सुनकर वह उठी तो कमरे का ताला टूटा मिला। अंदर बंधी चारों बकरियां गायब थीं। इनकी कीमत करीब 12 हजार रुपए है। इधर, सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खड़गवां चौकी के ग्राम केरता पंडोपारा में 22 नवंबर की रात करीब 2.30 बजे चोरी हुई। बालिंदर रजक के घर से तीन बकरा और दो बकरी चोरी कर लिए गए। इनकी कीमत करीब 40 हजार रुपए बताई गई है। वहीं, उसी रात पड़ोसी रूपसाय गोंड के घर से भी दो बकरे पार कर दिए गए,जिनकी कीमत करीब 15 हजार रुपए है। पुलिस ने दोनों थाना क्षेत्रों में चोरी की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।

लापता किशोरी की तलाश में 30 हजार रुपए का इनाम घोषित

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र से लापता 16 वर्षीय किशोरी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। किशोरी की तलाश और अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आईजी दीपक झा ने 30 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। किशोरी की पतासाजी और आरोपी की गिरफ्तारी में मददगार सूचना देने वाले व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाएगा। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। सोनहत थाना क्षेत्र के रामगढ़ निवासी 16 वर्षीय किशोरी टहलने के लिए घर से निकली थी,लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों और रिश्तेदारों ने आसपास काफी तलाश की,लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। प्रथम दृष्टया नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका पर सोनहत थाने में अपराध दर्ज किया गया है। आईजी ने घोषणा की है कि किशोरी की पतासाजी और अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी में मददगार सूचना देने वाले व्यक्ति को 30 हजार रुपए नकद पुरस्कार दिया जाएगा। सूचना देने वाले का नाम और पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

कृषि विभाग की कार्रवाई : बलरामपुर के कृषि सेवा केंद्र से 7.39 क्विंटल बीज और कीटनाशक जब्त

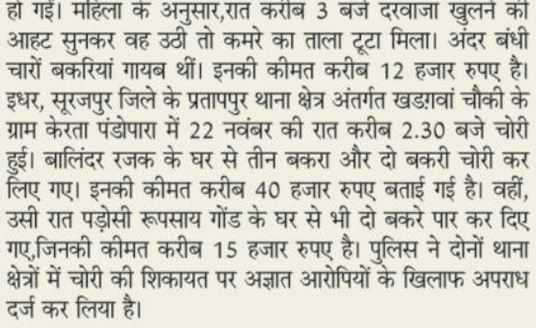

-संवाददाता-
बलरामपुर,25 नवंबर 2026(घटती-घटना)।

किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज, उर्वरक और कीटनाशक उचित दर पर मिलें, और कृषि आदान की बिक्री में पारदर्शिता रहे, इसके लिए कृषि विभाग जिले के कृषि सेवा केंद्रों और कृषि आदान विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रहा है। इसी क्रम में विकासखंड बलरामपुर में स्थित कृपा कृषि सेवा केंद्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पता चला कि प्रतिष्ठान में बीज अधिनियम 1966 के प्रावधानों का उल्लंघन कर बीज बेचे जा रहे थे। इस पर विभाग ने वहां रखे विभिन्न कंपनियों के बीज जब्त किए। इनमें 5 क्विंटल गेहूं,1.55 क्विंटल सरसों और 0.84 क्विंटल मक्का के बीज शामिल हैं। प्रतिष्ठान में कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं 1979 के प्रावधानों का उल्लंघन भी मिला। इस पर विभिन्न कंपनियों के कुल 42 लीटर तरल कीटनाशक और 25 किलोग्राम अन्य कीटनाशक उत्पाद जब्त किए गए। विभाग ने प्रतिष्ठान संचालक को निर्देश दिए हैं कि जब्त बीज और कीटनाशक अगले आदेश तक न बेचे जाएं और न ही उन्हें भंडारण स्थल से हटाया जाए। वैध अनुज्ञप्ति और निर्धारित नियमों के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।

रेस्क्यू के बाद लौटी टीम,अब रेडियो कॉलर से ट्रैक होगा कबरा का हर मूवमेंट

19 लोगों की जान लेने वाले हाथी की आक्रामकता में आई कमी,17 हाथियों के दल में हुआ शामिल...15 दिन तक उदयपुर के जंगलों में चला अभियान







-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

छह महीने में 19 लोगों की जान लेने वाले कबरा हाथी के रेस्क्यू के बाद अब वन विभाग की नजर उसकी हर गतिविधि पर रहेगी। ट्रैंकुलाइज कर रेडियो कॉलर पहनाए जाने के बाद कबरा दोबारा 17 हाथियों के दल में शामिल हो गया है। वनकर्मियों के अनुसार,उसकी आक्रामकता में भी कमी आई है और फिलहाल वह शांत व्यवहार कर रहा है। रेडियो कॉलर के जरिए उसकी लोकेशन ट्रैक की जाएगी, ताकि आबादी की ओर उसकी आवाजाही का समय रहते पता लगाया जा सके। इधर, करीब 15 दिनों तक उदयपुर के जंगलों में रेस्क्यू अभियान चलाने वाली रमकोला और अचानकमार की टीमें बुधवार को वापस लौट गईं। कबरा हाथी पिछले छह महीने से सरगुजा संभाग में आतंक का पर्याय बना हुआ था। उसके हमलों में अविभाजित सरगुजा जिले में 19 लोगों की मौत हो चुकी थी। लगातार बढ़ती जनहानि को देखते हुए वन विभाग ने उसे ट्रैंकुलाइज कर रेडियो कॉलर लगाने का निर्णय लिया था। इसके लिए वन विशेषज्ञों की टीम ने कुमकी हाथियों तीरथ राम और दुर्योधन की मदद ली। 19 नवंबर की सुबह करीब 8.30 बजे टीम उदयपुर के जंगल पहुंची। उस समय कबरा 17 हाथियों के दल के साथ था। उसे दल से अलग करने के लिए आतिशबाजी की गई। इसके बाद दोपहर करीब 12.30 बजे रामगढ़ पहाड़ी के नीचे जंगल में ट्रैंकुलाइज गन से उसे डॉट मारा गया। दवा का असर होने पर वह धीरे-धीरे बेहोश होने लगा। इसके बाद टीम ने उसके गले में रेडियो कॉलर लगाया और उसे वापस जंगल में छोड़ दिया।

तमोरपिंगला रेस्क्यू सेंटर लौटी टीम : रेस्क्यू अभियान में शामिल रमकोला और अचानकमार की टीम बुधवार को कुमकी हाथियों तीरथ राम और दुर्योधन के साथ तमोरपिंगला रेस्क्यू सेंटर लौट गई। करीब दो सप्ताह तक जंगल में कबरा की गतिविधियों पर नजर रखने और उसे सुरक्षित तरीके से ट्रैंकुलाइज करने के लिए टीम जुटी रही। अभियान पूरा होने के बाद टीम के सदस्यों के चेहरों पर राहत और अपने परिवार से मिलने की खुशी साफ नजर आई।

ज्वेलर्स दुकान का ताला तोड़कर 90 हजार के आभूषण चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

साथियों के साथ मिलकर दिया था वारदात को अंजाम,आरोपी की निशानदेही पर झाड़ियों से आर्टिफिशियल हार और एक जोड़ी झुमके बरामद,पुराने आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर बीएनएस की धारा 111 भी जोड़ी गई...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

गांधीनगर थाना क्षेत्र में ज्वेलर्स दुकान का ताला तोड़कर आभूषण चोरी करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी किए गए सामान में से एक आर्टिफिशियल हार और कान के एक जोड़ी झुमके बरामद कर जप्त किए हैं। चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब 90 हजार रुपये बताई गई है। मामले में आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड सामने आने पर पुलिस ने प्रकरण में बीएनएस की धारा 111 भी जोड़ी है। वहीं, वारदात में शामिल अन्य आरोपियों और शेष चोरी के सामान की तलाश जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, नवापारा नेहरू छात्रावास के पीछे निवासी निधि सोनी ने गांधीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 29 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 के मध्य अज्ञात व्यक्ति ने उनकी ज्वेलर्स दुकान को निशाना बनाया। आरोपी ने दुकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और वहां रखे चांदी



के 15 ब्रेसलेट सहित आर्टिफिशियल ज्वेलरी चोरी कर फरार हो गया। चोरी गए सामान की कीमत लगभग 90 हजार रुपये आंकी गई थी। शिकायत के आधार पर गांधीनगर पुलिस ने अपराध क्रमांक 616/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 331(4) एवं 305(ए) के तहत अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में जानकारी जुटाने के साथ मुखबिरों को भी सक्रिय किया। इसी बीच मुखबिर से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने संदेही शिवांग चौहान उर्फ राहुल (20 वर्ष), निवासी सोनी मोहल्ला,तालाब के पास गांधीनगर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक,संदेही से बारीकी से पूछताछ करने पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ज्वेलर्स दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। इसके बाद आरोपी की निशानदेही पर चोरी किए गए सामान में से एक आर्टिफिशियल हार और कान के झुमके की एक जोड़ी झाड़ियों में छिपाकर रखे स्थान से बरामद की गई। पुलिस ने दोनों वस्तुओं को विधिवत जप्त कर लिया है।

पुराने आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर बढ़ाई गई कार्रवाई : पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पूर्व में भी अपने साथियों के साथ चोरी की घटनाओं में संलिप्तता सामने आई है। इसी आधार पर वर्तमान प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 भी जोड़ी गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया जा रहा है। हालांकि,चोरी गए चांदी के 15 ब्रेसलेट सहित अन्य सामान की बरामदगी और वारदात में शामिल बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी अभी शेष है। पुलिस टीम इस दिशा में लगातार पतासाजी कर रही है।

खालिबा में मतदाता पंजीयन जागरूकता शिविर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष दिवा शिविर आयोजित



-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

श्री सांई बाबा आदर्श महाविद्यालय डिगमा में मंगलवार को स्वीप एवं निर्वाचन साक्षरता क्लब एवं एनएसएस टीम द्वारा ग्राम पंचायत खालिबा में राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष दिवा शिविर, मतदाता पंजीयन एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्ण सहभागिता ली। इस दौरान नए मतदाताओं के पंजीयन हेतु फॉर्म-6 की जानकारी एवं प्रक्रिया के बारे में बताया गया।मतदाता सूची में संशोधन हेतु फॉर्म-8 भरवाए गए तथा मतदान के महत्व एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान स्वच्छता, नशामुक्ति एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में हस्त कार्यक्रम अधिकारी श्री देवेंद्र दास सोनवानी एवं स्वीप नोडल अधिकारी श्री सुमन मिंज के नेतृत्व में किया गया। शिविर को सफल बनाने में सहायक प्राध्यापक श्री कृष्ण राम चौहान,कैंपस एम्बेसडर निशा निषाद एवं चंद्र प्रकाश राजवाड़े सहित स्वीप एवं श्रेष्ट टीम के स्वयंसेवकों ने सक्रिय योगदान दिया।

लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र में 19.32 करोड़ रुपये की लागत से बनेंगी दो सड़कें,विधायक प्रबोध मिंज ने किया भूमिपूजन

10 किलोमीटर लंबी सड़कों का होगा निर्माण, ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलने के साथ विकास को मिलेगी गति

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

जिले के लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया गया। मंगलवार को लोक निर्माण विभाग (भ/स),अंबिकापुर द्वारा आयोजित भूमिपूजन एवं कार्य शुभारंभ कार्यक्रम में लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने दोनों सड़कों का भूमिपूजन कर निर्माण कार्यों की शुरुआत की। इन दोनों सड़क निर्माण कार्यों की कुल लंबाई 10 किलोमीटर है तथा इन पर लगभग 19 करोड़ 33 लाख रुपये की लागत आएगी। इसके अंतर्गत असकला झेराडीह से बरगीडीह तक 5.80





किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 11 करोड़ 47 लाख 80 हजार रुपये की लागत से किया जाएगा। वहीं कोरंधा से पसेना तक 4.20 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 7 करोड़ 85 लाख 5 हजार रुपये की लागत से होगा। इस अवसर पर विधायक प्रबोध मिंज ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सड़कें ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण आधारशिला बन रही हैं। बेहतर सड़क संपर्क से ग्रामीणों को आवागमन के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं तक पहुंचने में सहूलियत मिलती है। इन सड़कों के निर्माण से क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी तथा विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरुपा सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष देव नारायण यादव, जनपद अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पावले,विधायक प्रतिनिधि जयंत मिंज,अरविंद गुप्ता,इन्द्रदेव गुप्ता,हलीम फिरदौसी सहित विभागीय अधिकारी, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि,पंचायत प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।

CMYK



कलेक्टर के सामने खुलती बच्चों के मन की गांठें, 'सुपर थर्टी' में सपनों के साथ घर की पीड़ा भी साझा कर रहे युवा

कलेक्टर के सामने बेझिझक खुल रहे बच्चों के सपने, 'सुपर-30' बना संवाद और मार्गदर्शन का मंच





झुमका के तट पर सजी 'सुपर-30' की पाठशाला,कलेक्टर से सीधे सवाल पूछ रहे युवा

कलेक्टर से लक्ष्य पूछते युवा,घर की परेशानियां भी साझा करते बच्चे; 'सुपर-30' की अनूठी पहल

किताबी पढ़ाई से आगे जिंदगी का पाठ,कलेक्टर रोक्तिमा यादव से रूबरू हुए 30 युवा

हर महीने 30 नए युवाओं को मिलता है सीधे संवाद का अवसर,रोजगार, उद्यमिता,भविष्य के लक्ष्य और पारिवारिक समस्याओं पर खुलकर होती है बातचीत

-संवाददाता-

बैकुंठपुर (कोरिया),25 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

आमतौर पर किसी जिले के कलेक्टर से मिलने या अपनी बात कहने के लिए लोगों को आवेदन, मुलाकात का समय और औपचारिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है,लेकिन कोरिया जिले में एक ऐसा मंच तैयार किया गया है, जहां बच्चे और युवा बिना किसी शिक्षक या मध्यस्थ के सीधे कलेक्टर के सामने बैठकर अपने मन की बात कह सकते हैं, वे उनसे अपने भविष्य,लक्ष्य,पढ़ाई,रोजगार और जीवन की चुनौतियों पर सवाल पूछते हैं,इतना ही नहीं, कुछ बच्चे अपने घर की परिस्थितियों और परिवार में नशे के कारण पैदा हुई परेशानियों को भी खुलकर साझा करते हैं,यह मंच है कलेक्टर्स-15 का 'सुपर थर्टी',जहां हर महीने 30 नए बच्चों को अपनी बात रखने,सवाल पूछने और अपनी झिझक से बाहर निकलने का अवसर मिलता है।

बिना शिक्षक और मध्यस्थ के सीधे कलेक्टर से सवाल-

इस कार्यक्रम की सबसे खास बात इसका खुला और सहज स्वरूप है, सामान्यतः विद्यार्थी किसी बड़े अधिकारी के सामने अपनी बात रखने में संकोच करते हैं, कई बार उनके मन में सवाल होते हैं, लेकिन उन्हें पूछने का आत्मविश्वास नहीं होता, 'सुपर थर्टी' में बच्चों को इसी झिझक से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, यहां बच्चे सीधे कलेक्टर से पूछ लेते हैं कि उनका अपना लक्ष्य क्या है, वे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए, वे कलेक्टर से यह भी पूछते हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए कौन-से कदम उठाने चाहिए, मुश्किल परिस्थितियों में हौसला कैसे बनाए रखना चाहिए और उपलब्ध अवसरों का उपयोग किस तरह करना चाहिए, कलेक्टर रोक्तिमा यादव के सामने बच्चे अपने सवाल रखते हैं और उनके जवाब सुनते हैं, इस दौरान उन्हें यह एहसास कराया जाता है कि सवाल पूछना कमजोरी नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी है, किसी बड़े अधिकारी से सीधे संवाद करने का अनुभव बच्चों के भीतर आत्मविश्वास पैदा करने के साथ उन्हें अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने का अवसर भी देता है।

जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र गुप्ता की पहल पर सुपर-30 की तर्ज पर शुरू की गई '30 युवा, 30 सोच, 30 संभावना' की यह अवधारणा युवाओं को केवल किताबी ज्ञान या औपचारिक मार्गदर्शन तक सीमित नहीं रखती,बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी से जुड़े वास्तविक सवालों के साथ सामने आने का अवसर देती है,झुमका जलाशय के तट स्थित ओपन थिएटर में आयोजित इस कार्यक्रम में कलेक्टर कोरिया रोक्तिमा यादव स्वयं युवाओं के बीच बैठकर उनकी बातें सुनती हैं, यहां कलेक्टर और बच्चों के बीच संवाद का ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास है, जिसमें बच्चे बिना संकोच सवाल पूछ सकें और अपनी बात कह सकें।

जब बच्चे पढ़ाई से आगे बढ़कर घर की परेशानियां भी बताते हैं-'सुपर थर्टी' का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण पक्ष तब सामने आता है,जब कुछ बच्चे अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को भी साझा करते हैं, कई बार होनहार और प्रतिभाशाली बच्चे पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उनके घर का वातावरण उनकी राह में बाधा बन जाता है,कुछ बच्चों के परिवारों में नशे की समस्या के कारण घरेलू माहौल प्रभावित है,ऐसी परिस्थितियों का असर बच्चों की पढ़ाई,मानसिक स्थिति,आत्मविश्वास और भविष्य की योजनाओं पर भी पड़ता है,इन बच्चों के लिए अपनी परेशानी किसी के सामने रख पाना भी आसान नहीं होता,लेकिन इस मंच पर उन्हें अपनी बात कहने का अवसर मिलता है,वे बता पाते हैं कि उनके घर में क्या परिस्थितियां हैं,किन समस्याओं से वे जूझ रहे हैं और उनका भविष्य किन चुनौतियों के बीच आगे बढ़ रहा है,यह पहल इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि बच्चों की समस्याओं को केवल परीक्षा परिणाम या पढ़ाई में प्रदर्शन के आधार पर नहीं देखा जा रहा,बल्कि उनके सामाजिक और पारिवारिक परिवेश को समझने का भी प्रयास हो रहा है, प्रतिभा होने के बावजूद यदि किसी बच्चे को घर की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है,तो उसके लिए केवल पढ़ाई की सलाह पर्याप्त नहीं हो सकती,उसे सुनने,समझने और जरूरत के अनुसार सहयोग का रास्ता तलाशने की भी आवश्यकता होती है।

हर महीने 30 नए बच्चे, हर बार नए सवाल और नई सोच-इस आयोजन की एक विशेष व्यवस्था यह है कि हर महीने 30 नए बच्चों को शामिल किया जाता है,यानी हर बार नए चेहरे,नए अनुभव,नई सोच और अलग-अलग सवाल इस मंच का हिस्सा बनते हैं, इससे अधिक से अधिक बच्चों को सीधे संवाद का अवसर मिल सकता है,हर बच्चे की परिस्थिति अलग है,किसी का सवाल पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर है,कोई रोजगार और भविष्य की संभावनाओं को समझना चाहता है,तो कोई अपने परिवार की परिस्थितियों के बीच आगे बढ़ने का रास्ता तलाश रहा है, कुछ बच्चों के मन में ऐसे सवाल भी होते हैं, जिन्हें वे सामान्य कक्षा या दूसरे औपचारिक मंचों पर पूछने से झिझकते हैं। यहां उन्हें अपनी बात रखने की स्वतंत्रता मिलती है,इस तरह 'सुपर थर्टी' केवल 30 बच्चों की एक बैठक नहीं,बल्कि लगातार नए बच्चों तक पहुंचने और उनकी सोच को समझने की मासिक पहल बन रही है,हर महीने नए बच्चों को शामिल करने से संवाद का दायरा भी बढ़ता है और अलग-अलग पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की समस्याओं और संभावनाओं को जानने का अवसर मिलता है।



हंसी-मजाक से शुरू होकर गंभीर सवालों तक पहुंचता है संवाद-कार्यक्रम का वातावरण जानबूझकर सहज रखा जाता है, शुरुआत आपसी परिचय,हंसी-मजाक और हल्की-फुल्की बातचीत से होती है,ताकि बच्चे किसी औपचारिक बैठक का दबाव महसूस न करें,धीरे-धीरे बातचीत उनके सपनों, रुचियों,पढ़ाई,लक्ष्य,रोजगार और पारिवारिक परिस्थितियों तक पहुंचती है,अलग-अलग महाविद्यालयों और संस्थाओं से आने वाले बच्चों को एक-दूसरे को जानने और अपने विचार साझा करने का अवसर भी मिलता है, नए परिचय बनते हैं,आपसी संवाद बढ़ता है और बच्चे दूसरों की सोच तथा अनुभवों से भी सीखते हैं,गंभीर चर्चाओं के साथ रचनात्मकता, हंसी-मजाक और यादगार पलों का मेल इस आयोजन को सामान्य मार्गदर्शन कार्यक्रमों से अलग पहचान देता है।

उद्यमिता,रोजगार और अपने जिले में संभावनाओं की तलाश-कार्यक्रम में युवाओं के व्यक्तिगत लक्ष्यों के साथ कोरिया जिले में उपलब्ध अवसरों पर भी चर्चा होती है, उद्यमिता,स्वरोजगार,रोजगार और स्थानीय संसाधनों के आधार पर नए काम शुरू करने की संभावनाओं को समझने का प्रयास किया जाता है,युवाओं को यह सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे अपने कौशल और विचारों के माध्यम से अपने भविष्य के साथ जिले के विकास में भी योगदान दे सकते हैं, इसका उद्देश्य केवल बच्चों को बड़े सपने दिखाना नहीं,बल्कि उन सपनों तक पहुंचने के रास्तों पर बातचीत करना है,वे कौन-सी क्षमता विकसित करें, किस दिशा में तैयारी करें और अपने आसपास उपलब्ध अवसरों को कैसे पहचानें–ऐसे सवाल इस संवाद को व्यावहारिक बनाते हैं।

कलेक्टर तक पहुंचने का नहीं,अपनी बात कहने का आत्मविश्वास

किसी बच्चे के लिए कलेक्टर जैसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के सामने बैठकर बिना झिझक सवाल पूछ पाना अपने आप में एक बड़ा अनुभव है,इससे बच्चों के मन में प्रशासन और अधिकारियों को लेकर बनी औपचारिक दूरी कम हो सकती है,वे समझते हैं कि उनकी बात भी सुनी जा सकती है और उनके सवाल भी महत्वपूर्ण हैं,इस मंच की वास्तविक सफलता केवल इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि कितने बच्चे इसमें शामिल हुए, बल्कि इस बात से भी कि कितने बच्चे अपनी झिझक छोड़कर खुलकर बोल पाए,कितनों को अपने लक्ष्य की दिशा समझने में मदद मिली और कितनी पारिवारिक या व्यक्तिगत समस्याओं को पहचानकर आगे सहयोग का रास्ता बनाया जा सका,जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र गुप्ता की पहल और कलेक्टर रोक्तिमा यादव की बच्चों के साथ सीधे संवाद की भागीदारी से यह मंच एक ऐसी सोच को सामने रखता है,जिसमें बच्चों को केवल भविष्य का नागरिक नहीं, बल्कि वर्तमान में अपनी सोच और सवाल रखने वाला सक्रिय भागीदार माना जा रहा है,झुमका के तट पर हर महीने जुटने वाले 30 नए बच्चों के साथ यह पहल एक महत्वपूर्ण संदेश देती है–हर बच्चे के पास एक सपना है, हर सपने के पीछे एक कहानी है और हर कहानी को सुने जाने का अवसर मिलना चाहिए। कई बार किसी बच्चे को आगे बढ़ने के लिए बड़े संसाधनों से पहले किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है, जो उसकी बात धैर्य से सुने, उसके सवालों का जवाब दे और उसे यह भरोसा दिलाए कि उसकी परिस्थितियां चाहे जैसी हों,आगे बढ़ने की संभावनाएं हमेशा मौजूद हैं।

सिक्योरिटी गार्ड का मोबाइल हैंग होते ही खाते से निकल गए 1.12 लाख रुपए,यूको बैंक खाते से दो दिन में निकली रकम

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,25 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

मोबाइल हैंग होने के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड के बैंक खाते से 1 लाख 12 हजार रुपए निकलने का मामला सामने आया है। पीड़ित के अनुसार, 7 और 8 नवंबर के बीच उसके यूको बैंक खाते से अज्ञात व्यक्ति ने रकम दूसरे खाते में ट्रांसफर कर ली। पीड़ित ने मामले की शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार श्याम सुंदर टोप्पो (33) ग्राम बादा, थाना शंकरगढ़ का निवासी है और वर्तमान में अंबिकापुर के महामाया मंदिर में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्यरत है। उसने शिकायत में बताया है कि 7 और 8 नवंबर 2026 के बीच उसका मोबाइल अचानक हैंग हो गया था।

UPSC की तैयारी के लिए छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिलेगा दिल्ली में कोचिंग का अवसर,290 सीटों पर आवेदन आमंत्रित

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,25 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ शासन की CG-ACE योजना 2026 के अंतर्गत 'शिखर (भाग-1)' योजना के तहत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नई दिल्ली में UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। योजना में कुल 290 सीटें निर्धारित की गई हैं, जिनमें ST वर्ग के लिए 150, SC के लिए 60 और OBC के लिए 80 सीटें शामिल हैं। प्रत्येक वर्ग में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 06 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में त्रुटि सुधार की सुविधा 01 से 04 दिसंबर तक रहेगी, जबकि प्राक्चयन परीक्षा 13 दिसंबर 2026 को संभावित है। अभ्यर्थी आवेदन एवं योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट http://hmstribal.cg.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।

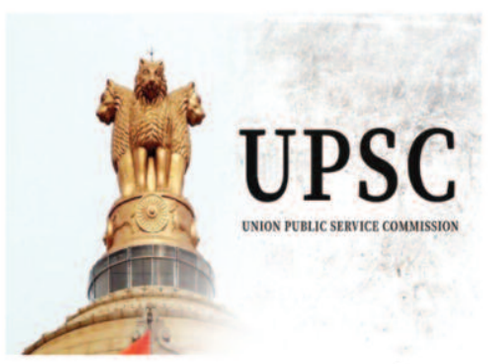

26 नवंबर को जनकपुर में मनाया जाएगा जिला स्तरीय संविधान गौरव दिवस,भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता होंगे शामिल

-संवाददाता-

मनेन्द्रगढ़,25 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।



भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार 26 नवंबर को जिला स्तरीय संविधान गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा, कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 12 बजे शासकीय नवीन महाविद्यालय,जनकपुर में निर्धारित किया गया है, उक्त आशय की जानकारी देते हुये भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राम चरित द्विवेदी ने बताया कि इस अवसर पर जिले में निवासरत भाजपा के प्रदेश एवं जिला पदाधिकारी,भाजपा के विभिन्न मोर्चा एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारी,कार्यसमिति सदस्य,जनप्रतिनिधि, नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि,वरिष्ठजन, प्रबुद्धजन, भाजपा कार्यकर्ता एवं आम नागरिकों को आमंत्रित किया गया है, संविधान गौरव दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान के महत्व,उसके मूल्यों,लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा संविधान निर्माताओं के योगदान को स्मरण किया जाएगा,आयोजन के माध्यम से संविधान के प्रति सम्मान एवं जागरूकता का संदेश दिया जाएगा, कार्यक्रम के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती चम्पा देवी पावले, जिला महामंत्री द्वारिका जायसवाल एवं आशीष मजूमदार, जिला संयोजक विधि प्रकोष्ठ आदित्य गुप्ता तथा जिला कार्यालय मंत्री रमेश यादव ने जिले के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों से कार्यक्रम में उपस्थित होने की अपील की है।



बैकुंठपुर में आशीष यादव के 13 संकल्पों से चुनावी हलचल तेज, पूर्व नगर सैनिक बनाम सीए का डिजिटल विजन!

'लल्ला का संकल्प पत्र 2026' में बस स्टैंड के कायाकल्प से लेकर स्विमिंग पूल,सियान सदन,व्यावसायिक परिसर और स्वच्छ पेयजल तक की योजनाएं शामिल,भाजपा के संभावित दावेदार प्रशांत गुप्ता पहले ही सामने रख चुके हैं डिजिटल बैकुंठपुर की परिकल्पना

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर,25 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर के आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां अब केवल संभावित प्रत्याशियों की दावेदारी तक सीमित नहीं रह गई हैं,भाजपा और कांग्रेस की ओर से संभावित चेहरों के साथ विकास के प्रस्ताव भी सार्वजनिक होने लगे हैं,कांग्रेस की ओर से वर्तमान नगर पालिका उपाध्यक्ष आशीष यादव उर्फ लाला ने अपने नाम से 'लल्ला का संकल्प पत्र 2026' जारी कर शहर के विकास के लिए 13 सूत्रीय कार्ययोजना सामने रखी है, वहीं भाजपा की ओर से अध्यक्ष पद के संभावित दावेदार सीए प्रशांत गुप्ता डिजिटल बैकुंठपुर का विजन प्रस्तुत कर चुके हैं,दोनों गतिविधियों ने बैकुंठपुर के चुनावी विमर्श को एक नया रूप दे दिया है,एक तरफ आशीष यादव ने शहर की भौतिक सुविधाओं, व्यापारिक गतिविधियों, खेल,पर्यटन, पेयजल और बुजुर्गों के लिए सुविधाओं का खाका पेश किया है,तो दूसरी तरफ प्रशांत गुप्ता का जोर नगर पालिका की सेवाओं को मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर है,इस तरह संभावित चुनावी मुकाबले में दो अलग-अलग विकास दृष्टिकोण सामने दिखाई देने लगे हैं।

आशीष यादव के संकल्प पत्र की खास बात यह है कि इसमें केवल सामान्य विकास के वादे नहीं हैं,बल्कि शहर के कुछ खास स्थानों और मौजूदा जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं रखी गई हैं,पुराने और नए बस स्टैंड, कुमार चौक से सोसाइटी गली,चौपाटी, रामानुज क्लब,रामानुज मिनी स्टेडियम और चेर तालाब जैसे स्थानीय स्थलों का उल्लेख किया गया है, इसके साथ शासकीय खाली जमीनों पर व्यावसायिक परिसर,स्विमिंग पूल क्लब, सियान सदन और प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने जैसे प्रस्ताव भी शामिल हैं,पोस्टरों की श्रृंखला में कांग्रेस का चुनाव चिह्न,बैकुंठपुर नगर पालिका चुनाव 2026 और आशीष यादव का नाम प्रमुखता से दिया गया है,इससे उनकी राजनीतिक दावेदारी और चुनावी तैयारी को सार्वजनिक रूप से सामने रखने की कोशिश दिखाई देती है,हालांकि, संकल्प पत्र जारी करना अधिकृत प्रत्याशी घोषित होने का प्रमाण नहीं है, टिकट को लेकर अंतिम निर्णय पार्टी संगठन की औपचारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।

13 संकल्पों में शहर की तस्वीर बदलने का दावा

1. पुराने एवं नए बस स्टैंड का कायाकल्प-पहला संकल्प शहर के पुराने और नए बस स्टैंड के जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण और व्यवस्थित विकास से जुड़ा है, बस स्टैंड किसी भी शहर की सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र होता है,यात्रियों के बैठने, पेयजल, शौचालय,प्रकाश व्यवस्था, प्रतीक्षालय और बसों के संचालन जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाना जरूरी है,इस संकल्प के जरिए दोनों बस स्टैंडों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने की बात कही गई है, अब सवाल यह होगा कि इस कार्य के लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी,उपलब्ध भूमि का उपयोग किस तरह होगा और दोनों बस स्टैंडों के विकास की प्राथमिकता क्या तय की जाएगी।

2. सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित व्यापारियों को प्राथमिकता से दुकानें-दूसरा संकल्प सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित व्यापारियों के पुनर्वास से जुड़ा है,पोस्टर में हाई स्कूल के समीप प्रस्तावित व्यावसायिक परिसर में प्रभावित व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर दुकानें उपलब्ध कराने की बात कही गई है,यह प्रस्ताव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सड़क चौड़ीकरण और शहरी विकास की प्रक्रिया में छोटे व्यापारियों की आजीविका प्रभावित हो सकती है,ऐसे में प्रभावित दुकानदारों को व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराने का सवाल नगर विकास के साथ सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास से भी जुड़ता है,हालांकि, दुकान आवंटन के लिए पात्रता, प्राथमिकता का आधार,लागत और प्रक्रिया स्पष्ट करना भी जरूरी होगा।

3. कुमार चौक से सोसाइटी गली तक दुकानों का विकास- तीसरे संकल्प में कुमार चौक से सोसाइटी गली तक दुकानों के गहरीकरण एवं पुनर्विकास के साथ दोमंजिला व्यावसायिक दुकानों के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाना बताया गया है, यदि यह योजना आगे बढ़ती है,तो स्थानीय व्यापारियों, ग्राहकों और यातायात व्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा,इसके लिए मौजूदा दुकानों की स्थिति, भूमि की उपलब्धता, पार्किंग और निर्माण के दौरान व्यापारियों को होने वाली असुविधा जैसे पहलुओं पर भी योजना बनानी होगी।

4. चौपाटी का स्थानांतरण और सौंदर्यीकरण-चौथा संकल्प चौपाटी को बस स्टैंड तालाब के समीप स्थानांतरित कर मरीन ड्राइव की तर्ज पर आकर्षक सौंदर्यीकरण और व्यवस्थित खान-पान क्षेत्र विकसित करने का है,यह प्रस्ताव शहर में मनोरंजन और खान-पान की बेहतर व्यवस्था बनाने की परिकल्पना करता है,यदि चौपाटी को व्यवस्थित स्थान पर विकसित किया जाता है, तो इससे स्थानीय दुकानदारों और छोटे व्यवसायियों के लिए अवसर बन सकते हैं,लेकिन इसके साथ साफ-सफाई, पार्किंग,सुरक्षा,कचरा प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा जैसी व्यवस्थाएं भी आवश्यक होंगी।

5. रामानुज क्लब का जीर्णोद्धार और खेल सुविधाओं का विस्तार-पांचवें संकल्प में रामानुज क्लब का जीर्णोद्धार कर बैडमिंटन और टेबल टेनिस खिलाड़ियों के लिए बेहतर खेल वातावरण उपलब्ध कराने की बात है। पोस्टर में साफ,स्वस्थ और सुविधायुक्त खेल परिसर की परिकल्पना दिखाई गई है,शहर के युवाओं और खेल प्रतिभाओं के लिए यह प्रस्ताव उपयोगी हो सकता है,लेकिन इसके लिए खेल उपकरण,प्रशिक्षक,रखरखाव,सदस्यता और खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं की स्पष्ट योजना बनाना जरूरी होगा।

6. सरकारी खाली जमीनों पर व्यावसायिक परिसर-छठे संकल्प में शहर के मध्य स्थित शासकीय खाली भूमि का उपयोग कर व्यावसायिक परिसर बनाने का प्रस्ताव है, इसका उद्देश्य स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर तैयार करना बताया गया है,यह योजना अपने आप में कई प्रशासनिक सवाल भी खड़े करती है,शासकीय भूमि की उपलब्धता,उसका वर्तमान उपयोग, संबंधित विभागों की अनुमति,भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने की वैधानिक प्रक्रिया और निर्माण में लगने वाली राशि जैसे पहलुओं का समाधान किए बिना ऐसे प्रस्ताव को अमल में लाना आसान नहीं होगा, इसलिए इस संकल्प की व्यवहारिकता भूमि के वास्तविक रिकॉर्ड और स्वीकृतियों पर निर्भर करेगी।

7. सर्वसुविधायुक्त स्विमिंग पूल क्लब-सातवें संकल्प में शहर के भीतर आधुनिक और सर्वसुविधायुक्त स्विमिंग पूल क्लब स्थापित करने की बात कही गई है,इसमें युवाओं,बच्चों और नागरिकों के लिए तैराकी तथा स्वस्थ जीवनशैली से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है,यह शहर के लिए एक नई सुविधा हो सकती है,लेकिन स्विमिंग पूल के निर्माण के साथ पानी की उपलब्धता, नियमित रखरखाव,सुरक्षा,प्रशिक्षित लाइफगार्ड, बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था और संचालन खर्च जैसे विषय भी महत्वपूर्ण होंगे।

8. रामानुज मिनी स्टेडियम का पुनर्विकास

आठवें संकल्प में रामानुज मिनी स्टेडियम को बेहतर बनाने की बात है, पोस्टर में ग्रास कॉर्पेट, समुचित बैरिकेडिंग और व्यवस्थित पाथवे के साथ खेल एवं व्यायाम के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने का प्रस्ताव दिया गया है,स्टेडियम का विकास केवल मैदान को सुंदर बनाने तक सीमित नहीं होना चाहिए,खिलाड़ियों के लिए खेल सुविधाएं,दर्शकों की व्यवस्था,प्रकाश, सुरक्षा और नियमित रखरखाव भी जरूरी होंगे,यदि इस प्रस्ताव को विस्तृत योजना के साथ लागू किया जाता है,तो शहर की खेल गतिविधियों को बेहतर आधार मिल सकता है।

9. चेर तालाब का सौंदर्यीकरण और घाट निर्माण

नौवें संकल्प में चेर तालाब का सौंदर्यीकरण और घाट निर्माण शामिल है,प्रस्ताव के अनुसार तालाब को स्वच्छ,सुंदर और आकर्षक सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही गई है,तालाबों का संरक्षण केवल सौंदर्यीकरण तक सीमित नहीं होना चाहिए,जलस्रोत की सफाई, जल निकासी, गंदे पानी के प्रवेश पर नियंत्रण,घाटों की सुरक्षा और नियमित रखरखाव भी इसके आवश्यक हिस्से हैं। ऐसे कार्यों से तालाब का धार्मिक,सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व भी सुरक्षित रह सकता है।

10. बुजुर्गों के लिए सर्वसुविधायुक्त सियान सदन

दसवें संकल्प में शहर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सियान सदन बनाने का प्रस्ताव है,पोस्टर के अनुसार, यह ऐसा स्थान होगा जहां बुजुर्ग बैठ सकें,आपस में मिल-जुल सकें,मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सकें,तेजी से बदलती शहरी जीवनशैली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसे केंद्र उपयोगी हो सकते हैं,यहां बैठने,पेयजल,शौचालय,स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिक सहायता और मनोरंजन की सुविधाओं पर भी विचार करना होगा,इस प्रस्ताव का महत्व केवल भवन निर्माण में नहीं, बल्कि बुजुर्गों के लिए नियमित गतिविधियों और सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित करने में होगा।

11. डिजिटल सुविधा और त्वरित समाधान-ग्यारहवां संकल्प डिजिटल सुविधा और शिकायतों के त्वरित समाधान से जुड़ा है, पोस्टर में नल,बिजली,पानी,सफाई और अन्य नागरिक समस्याओं के लिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल बनाने की बात कही गई है, इसके तहत शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास और शिकायत की ऑनलाइन स्थिति जानने की सुविधा देने का उल्लेख है,यहां 24 घंटे के भीतर समाधान की बात को एक महत्वपूर्ण चुनावी वादे के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि सभी प्रकार की शिकायतों का वास्तविक समाधान 24 घंटे में संभव होगा या नहीं, यह समस्या की प्रकृति और संबंधित विभागों पर निर्भर करेगा। इसलिए शिकायत प्राप्ति,संबंधित अधिकारी को भेजने, समय-सीमा तय करने और समाधान की निगरानी की स्पष्ट व्यवस्था भी आवश्यक होगी।

12. स्वच्छ,सुंदर और सुव्यवस्थित शहर-बारहवें संकल्प में नियमित साफ-सफाई, कचरे का उचित प्रबंधन,सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए विशेष अभियान चलाने की बात कही गई है, यह ऐसा विषय है जो सीधे प्रत्येक नागरिक के दैनिक जीवन से जुड़ा है,इसमें केवल सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि कचरा संग्रहण,परिवहन, निस्तारण, नालियों की सफाई,सार्वजनिक शौचालय और नागरिकों की भागीदारी जैसे पहलुओं पर भी काम करना होगा।

13. प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल-तेरहवां और अंतिम संकल्प प्रत्येक वार्ड एवं मोहल्ले में स्वच्छ तथा पर्याप्त पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने से संबंधित है,पोस्टर में जल आपूर्ति व्यवस्था के विस्तार और सुधार के साथ जल संकट वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है, पेयजल शहर की सबसे बुनियादी जरूरतों में से एक है,इस संकल्प की सफलता के लिए जल स्रोत,जल वितरण नेटवर्क, पाइपलाइन,टंकियों की स्थिति,पानी की गुणवत्ता जांच और नियमित आपूर्ति की व्यवस्था महत्वपूर्ण होगी।

संकल्प पत्र में शहर के छोटे-बड़े मुद्दों को एक साथ साधने की कोशिश

13 संकल्पों को देखने पर स्पष्ट होता है कि आशीष यादव ने अपने प्रस्ताव में शहर के अलग-अलग वर्गों और जरूरतों को शामिल करने का प्रयास किया है, प्रभावित व्यापारियों के पुनर्वास से लेकर नए व्यावसायिक परिसरों तक व्यापारिक वर्ग को ध्यान में रखा गया है,रामानुज क्लब,मिनी स्टेडियम और स्विमिंग पूल के जरिए युवाओं तथा खेल प्रेमियों को संबोधित किया गया है,सियान सदन से बुजुर्गों, तालाब और चौपाटी के सौंदर्यीकरण से आम नागरिकों तथा स्वच्छ पेयजल और सफाई से प्रत्येक वार्ड के लोगों की अपेक्षाओं को संकल्पों में शामिल किया गया है,इस लिहाज से संकल्प पत्र का दायरा केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं है, इसमें नगर पालिका की सेवाओं, नागरिक सुविधाओं और शहरी जीवन की गुणवत्ता से जुड़े विषय भी शामिल हैं,लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि इन सभी योजनाओं का वित्तीय ढांचा क्या होगा? नगर पालिका के पास उपलब्ध संसाधनों से कितनी योजनाएं पूरी हो सकेंगी? किन कार्यों के लिए राज्य सरकार या अन्य विभागों से राशि और अनुमति लेनी होगी? इन प्रस्तावों की प्राथमिकता तय करने और उन्हें पूरा करने की समय-सीमा क्या होगी? यही वे सवाल हैं, जिनका स्पष्ट उत्तर मिलने पर संकल्प पत्र केवल चुनावी घोषणा न रहकर एक व्यावहारिक विकास योजना बन सकेगा।

पूर्व नगर सैनिक बनाम सीए-क्या इसी आधार पर बनेगा चुनावी विमर्श?

स्थानीय राजनीतिक चर्चा में आशीष यादव की पूर्व नगर सैनिक की पृष्ठभूमि और वर्तमान नगर पालिका उपाध्यक्ष की भूमिका का उल्लेख होता रहा है, दूसरी ओर, प्रशांत गुप्ता की पहचान चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में है और उनका डिजिटल विजन नगर प्रशासन को तकनीक से जोड़ने पर केंद्रित है, इसलिए चुनावी चर्चा में दो अलग-अलग व्यक्तित्व और विकास की दो अलग-अलग प्राथमिकताएं सामने रखी जा रही हैं, लेकिन किसी की शैक्षणिक या पेशेवर पृष्ठभूमि से अपने आप यह तय नहीं हो जाता कि वह नगर पालिका का बेहतर संचालन करेगा, इसके लिए प्रशासनिक समझ, वित्तीय प्रबंधन, जनसंपर्क, स्थानीय समस्याओं का अनुभव और योजनाओं को लागू करने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी, यह भी याद रखना जरूरी है कि दोनों के नाम अभी संभावित दावेदारों के रूप में चर्चा में हैं, अधिकृत टिकट की घोषणा के बिना मुकाबले को अंतिम रूप से तय मानना जल्दबाजी होगी।

संकल्पों की असली परीक्षा होगी बजट,समय-सीमा और क्रियान्वयन

बैकुंठपुर में 13 संकल्पों के पोस्टर जारी होने के बाद अब चर्चा केवल इस बात की नहीं रहेगी कि किसने कितने वादे किए, बल्कि यह भी होगी कि उन वादों को पूरा करने का रास्ता क्या है? क्या पुराने और नए बस स्टैंड का विकास प्राथमिकता में होगा? प्रभावित व्यापारियों को दुकानें आवंटित करने के लिए पात्रता और पुनर्वास की क्या प्रक्रिया होगी? सरकारी खाली जमीन पर व्यावसायिक परिसर बनाने के लिए अनुमति किससे मिलेगी? स्विमिंग पूल और सियान सदन के निर्माण के बाद उनका संचालन कौन करेगा? चेर तालाब के सौंदर्यीकरण के साथ जल संरक्षण कैसे सुनिश्चित होगा? पेयजल और डिजिटल शिकायतों के लिए समय-सीमा तथा जवाबदेही किस अधिकारी की होगी? इन सवालों का जवाब केवल चुनावी प्रचार से नहीं,बल्कि विस्तृत कार्ययोजना से ही मिल सकता है, नगर पालिका के बजट और संसाधनों की सीमा भी इन संकल्पों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

सीए प्रशांत गुप्ता का डिजिटल विजन भी चुनावी चर्चा में

कांग्रेस के संकल्प पत्र के बीच भाजपा की ओर से संभावित दावेदार सीए प्रशांत गुप्ता का डिजिटल बैकुंठपुर विजन भी चर्चा में है, उन्होंने पहले वीडियो जारी कर नगर पालिका की सेवाओं को मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ने की परिकल्पना सामने रखी थी,उनके प्रस्ताव में जन्म और अन्य प्रमाणपत्रों के आवेदन, भवन निर्माण अनुमति की स्थिति, सामुदायिक भवन की ऑनलाइन बुकिंग, निविदाओं की जानकारी,नागरिक सुझाव,नगर पालिका बजट की पारदर्शिता और ऑनलाइन शिकायत व्यवस्था जैसे विषय शामिल हैं,उनका जोर इस बात पर है कि नागरिकों को छोटी-छोटी सेवाओं के लिए बार-बार नगर पालिका कार्यालय न जाना पड़े और वे अपने मोबाइल से आवेदन तथा शिकायत की स्थिति देख सकें,इस संदर्भ में आशीष यादव के संकल्प पत्र का ग्यारहवां बिंदु भी ध्यान देने योग्य है, उन्होंने भी ऑनलाइन शिकायत पोर्टल और त्वरित समाधान की बात रखी है,इससे स्पष्ट है कि डिजिटल नागरिक सेवाएं अब बैकुंठपुर के संभावित चुनावी एजेंडे का भी हिस्सा बनने लगी हैं, हालांकि दोनों प्रस्तावों में अंतर है,आशीष यादव के दस्तावेज में डिजिटल शिकायत सुविधा 13 संकल्पों में से एक है,जबकि प्रशांत गुप्ता ने डिजिटल प्रशासन को अपने विजन का प्रमुख आधार बनाया है,दोनों ही प्रस्तावों की असली उपयोगिता इस बात से तय होगी कि वे कितनी व्यावहारिक व्यवस्था,समय-सीमा और जवाबदेही के साथ लागू किए जा सकते हैं।

अब टिकट से आगे विकास के दावों की परीक्षा

बैकुंठपुर नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस की ओर से आशीष यादव उर्फ लाला का 13 सूत्रीय संकल्प पत्र सामने आने के बाद उनकी दावेदारी को लेकर चर्चा तेज हुई है,वहीं भाजपा से सीए प्रशांत गुप्ता डिजिटल बैकुंठपुर का विजन प्रस्तुत कर चुके हैं, एक ओर शहर के भौतिक विकास, व्यापार,खेल,तालाब,पेयजल और बुजुर्गों की सुविधाओं का विस्तृत खाका है,तो दूसरी ओर नगर पालिका की सेवाओं को ऑनलाइन और अधिक पारदर्शी बनाने की परिकल्पना है,फिलहाल दोनों दलों की अधिकृत प्रत्याशी घोषणा बाकी है, लेकिन संभावित उम्मीदवारों ने अपने एजेंडे सार्वजनिक कर दिए हैं। अब राजनीतिक दलों के सामने टिकट तय करने के साथ-साथ यह भी चुनौती होगी कि वे अपने उम्मीदवारों के विकास प्रस्तावों को कितनी विश्वसनीयता और व्यवहारिकता के साथ जनता के सामने रखते हैं,बैकुंठपुर का चुनाव अब केवल चेहरों की दावेदारी तक सीमित नहीं रह गया है, 13 संकल्पों और डिजिटल बैकुंठपुर के विजन ने शहर के विकास को भी चुनावी चर्चा के केंद्र में ला दिया है,मतदाताओं के सामने अब बड़ा सवाल होगा—शहर के लिए प्रस्तुत योजनाओं में कौन-सी प्राथमिकताएं अधिक जरूरी हैं, कौन-से प्रस्ताव जमीन पर उतारे जा सकते हैं और कौन-सा संभावित नेतृत्व उन्हें पूरा करने की स्पष्ट कार्ययोजना रखता है,अंततः किसी भी संकल्प पत्र की असली कीमत उसके आकर्षक पोस्टरों से नहीं, बल्कि बजट,समय-सीमा,पारदर्शिता और काम पूरा करने की जवाबदेही से तय होगी।



सीईओ हो तो श्रीकांत चंद्राकर जैसा! 'अपनों' की फाइल पर नरमी, बाकी पर जांच की गर्मी?

35 साल पुरानी फाइल को मिली संजीवनी, करोड़ों की शिकायतों को अब तक ऑक्सीजन क्यों नहीं?

35 साल पुरानी नियुक्ति की फाइल खुलते ही कार्रवाई का अलार्म बजा, लेकिन 2020 से 2026 तक की करोड़ों की कथित वित्तीय अनियमितताओं पर सन्नाटा क्यों?...

जिसके सिर पर चंद्राकर का हाथ, उसकी फाइल साफ,जिसके खिलाफ हुए,उसकी कुंडली तत्काल बाहर!

2020 से 2026 तक की शिकायतें बेअसर, 1990-91 की फाइल पर अचानक जागा बैंक प्रशासन!

सीईओ साहब का घुनिंदा न्याय! करोड़ों की अनियमितताओं पर खामोशी,एक शिकायत पर जांच की रफ्तार तूफानी!

चहेतों की बहाली के लिए जांच दल, सवाल उठाने वालों पर कार्रवाई! बैंक में आखिर चल किसका रहा है खेल?

निर्मला तिवारी की जांच बनी ढाल या चंद्राकर का बचाव? पुराने मामलों की फाइलें अब भी धूल फांक रहीं!

बैंक में न्याय का नया पैमाना! पसंदीदा कर्मचारियों को संरक्षण,बाकी के लिए पुराने रिकॉर्ड की खुदाई!

शिकायतों का अंबार,कार्रवाई का अकाल! चंद्राकर के टेबल पर किसकी फाइल खुलेगी और किसकी दबेगी?

जांच के नाम पर किसे बचाने और किसे फंसाने की तैयारी? जिला सहकारी बैंक में चंद्राकर की कार्यशैली पर गंभीर सवाल!

निर्मला तिवारी की जांच रिपोर्ट के बाद सीईओ पर आरोप,जगदीश कुशवाहा की बहाली और जांच दल के गठन को लेकर भी उठे सवाल...

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर/अंबिकापुर,23 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर में इन दिनों जांच, शिकायत,नियुक्ति,बहाली और कार्रवाई को लेकर ऐसा प्रशासनिक घटनाक्रम सामने आ रहा है,जिसने बैंक की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं,यहां सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीकांत चंद्राकर के विरुद्ध शिकायतें क्यों हो रही हैं,बल्कि बड़ा सवाल यह है कि बैंक में शिकायतों पर कार्रवाई का पैमाना आखिर तय कौन कर रहा है? क्या हर शिकायत पर समान गंभीरता से जांच होती है,या फिर शिकायत और कार्रवाई के बीच भी कोई पसंद-नापसंद का समीकरण काम करता है? बैंक के सीईओ श्रीकांत चंद्राकर का पक्ष एक समाचार में सामने आया है कि उनके द्वारा अपने ही बैंक की एक कर्मचारी के विरुद्ध जांच कराई गई, जिसमें कई कमियां पाई गईं और इसी कारण उनके विरुद्ध षड्यंत्रपूर्वक शिकायतें की जा रही हैं,लेकिन इस दलील के साथ ही एक दूसरा सवाल भी खड़ा होता है–यदि जांच करना ही उनके विरुद्ध शिकायतों का कारण है,तो फिर बैंक में पिछले कई वर्षों से लंबित वित्तीय अनियमितताओं और गबन से संबंधित शिकायतों की जांच तथा कार्रवाई का हिसाब कौन देगा? बैंक के कामकाज पर नजर डालें तो वर्ष 2020 से 2026 के बीच विभिन्न शाखाओं और समितियों से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं, फसल बीमा, पशु ऋण वितरण और अन्य मामलों को लेकर शिकायतें तथा समाचार प्रकाशित हुईं,इनमें कुछ मामलों में करोड़ों रुपये की कथित अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए,ऐसे में सवाल है कि इन शिकायतों की जांच कहां तक पहुंची? किन मामलों में जांच प्रतिवेदन तैयार हुआ? दोषियों की जिम्मेदारी तय हुई या नहीं? और यदि कार्रवाई हुई तो उसका विवरण सार्वजनिक क्यों नहीं है? विडंबना देखिए कि एक ओर वर्षों पुरानी नियुक्ति से जुड़ी फाइल खोलकर जांच प्रतिवेदन तैयार किया जाता है,दूसरी ओर हाल के वर्षों की वित्तीय शिकायतों पर कार्रवाई की स्थिति को लेकर स्पष्ट जवाब सामने नहीं आता,आखिर जांच की यह रफ्तार सभी मामलों में क्यों नहीं दिखाई देती?



35 साल पुरानी फाइल खुली, लेकिन नई शिकायतों का क्या?

निर्मला तिवारी की नियुक्ति से संबंधित जांच प्रतिवेदन में वर्ष 1989 से 1993 तक के घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है, उपलब्ध प्रतिवेदन के अनुसार,17 नवंबर 1989 को पत्र क्रमांक 2716 के माध्यम से उन्हें 59 दिवस के लिए पूर्ण अस्थाई दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य पर रखा गया था,प्रतिवेदन में इस नियुक्ति के लिए आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल की अनुमति से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई है, इसके बाद 20 मार्च 1990 को पत्र क्रमांक 5133 से लिपिक पद पर नियुक्ति दी गई तथा 6 अप्रैल 1990 को कार्यभार ग्रहण कराया गया,प्रतिवेदन के अनुसार,संचालक मंडल की बैठक दिनांक 17 मार्च 1990 के निर्णय क्रमांक 9(4)(3) के आधार पर विकलांग महिला के रूप में नियुक्ति की गई थी, लेकिन इस नियुक्ति को लेकर आगे जो घटनाक्रम सामने आया, वह जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

नियुक्ति अस्वीकृत,सेवा समाप्त और अगले ही दिन आदेश निरस्त!

जांच प्रतिवेदन में उल्लेख है कि पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल ने बैंक के प्रस्ताव पत्र क्रमांक 3486 दिनांक 25 अप्रैल 1991 के संबंध में पत्र क्रमांक 4197 दिनांक 25 जून 1991 से नियुक्ति को अस्वीकृत किया था,इसके पालन में बैंक द्वारा 5 जुलाई 1991 को पत्र क्रमांक 57 जारी कर सेवाएं समाप्त कर दी गईं,लेकिन प्रतिवेदन के अनुसार,अगले ही दिन यानी 6 जुलाई 1991 को पत्र क्रमांक 81 के माध्यम से सेवा समाप्ति आदेश निरस्त कर दिया गया, आरोप यह है कि ऐसा करते समय पंजीयक की अनुमति और सूचना का पालन नहीं किया गया,इसके बाद 23 दिसंबर 1993 को पत्र क्रमांक 4238 से नियमितीकरण का आदेश जारी कर दिया गया,जांच प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि संबंधित नियुक्ति के लिए आवश्यक अनुमति का दस्तावेज बैंक के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं मिला,यहीं सवाल उठता है कि जिस नियुक्ति को पंजीयक स्तर पर अस्वीकृत किए जाने का उल्लेख है,उसी नियुक्ति की सेवा समाप्ति का आदेश अगले दिन कैसे निरस्त हुआ? नियमितीकरण किस प्रक्रिया और किस सक्षम अनुमति के आधार पर किया गया? यदि प्रक्रिया में अनियमितता थी तो इतने वर्षों तक इस पर जवाबदेही क्यों तय नहीं हुई?

पदोन्नति,स्थापना कक्ष और चार्ज नहीं सौंपने का मामला

प्रतिवेदन के अनुसार,निर्मला तिवारी को सेवा अवधि में दो पदोन्नतियां मिलीं, उन्हें सहायक लेखापाल और बाद में सहायक मुख्य पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नत किए जाने का उल्लेख है,प्रतिवेदन में उनकी अलग-अलग शाखाओं और कक्षों में पदस्थापना का विवरण भी दिया गया है,वसूली कक्ष में पांच वर्ष,फील्ड कक्ष में तीन वर्ष,स्थापना कक्ष में चार वर्ष,लेखा कक्ष में तीन वर्ष और इसके बाद 26 जुलाई 2021 से पुनः स्थापना कक्ष में पदस्थ रहने का उल्लेख है,जांच प्रतिवेदन के अनुसार,स्थापना कक्ष में उनकी कुल अवधि लगभग दस वर्ष बताई गई है,जबकि बैंक कर्मचारी सेवा नियम में एक स्थान पर अधिकतम तीन वर्ष की अवधि का प्रावधान होने की बात कही गई है,इसके अलावा 24 अगस्त 2026 से 30 अगस्त 2026 तक अवकाश आवेदन देने और उसके बाद अवकाश पर रहने का उल्लेख है, प्रतिवेदन में कहा गया है कि स्थापना कक्ष की फाइलों और दस्तावेजों का चार्ज नहीं सौंपा गया,इस संबंध में प्रधान कार्यालय द्वारा 19 सितंबर 2026 को पत्र क्रमांक 1914 तथा 29 सितंबर 2026 को स्मरण पत्र क्रमांक 2014 जारी किए जाने का उल्लेख है,यहां भी सवाल है कि यदि कार्यालय का महत्वपूर्ण चार्ज नहीं सौंपा गया था,तो इस स्थिति के समाधान के लिए समय रहते क्या कदम उठाए गए? और क्या इसकी जिम्मेदारी तय की गई?

जगदीश कुशवाहा प्रकरण:बहाली की कोशिश या जांच प्रक्रिया पर सवाल?- इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जगदीश कुशवाहा से संबंधित मामला है, उपलब्ध जानकारी और विभागीय सूत्रों के दावों के अनुसार, उनके विरुद्ध प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े लगभग 32 लाख रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया था,इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के बाद सेवा समाप्ति की कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है,इसके बाद उन्हें पुनः बहाल करने के उद्देश्य से जांच दल गठित किए जाने को लेकर विवाद सामने आया। बताया जा रहा है कि इस जांच दल में ऐसे कर्मचारियों को शामिल किया गया,जो पहले जांच कर चुके अधिकारियों से पदक्रम में नीचे थे,विभागीय सूत्रों का दावा है कि जांच दल में शामिल कुछ कर्मचारियों ने पहले से हुई उच्च स्तरीय जांच के निष्कर्षों के विपरीत पुनः जांच करने पर आपत्ति जताई और जांच करने से इनकार कर दिया, सूत्रों का आरोप है कि इसके बाद जांच करने से इनकार करने वाले कर्मचारियों को ही निशाने पर लिया जाने लगा, हालांकि इस पूरे मामले में जांच दल के गठन का आदेश,जांच से इनकार करने वाले कर्मचारियों के लिखित अभिमत और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का आधिकारिक विवरण सामने आना जरूरी है,सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध पहले ही उच्च स्तरीय जांच हो चुकी थी और सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया जा चुका था, तो पुनः जांच की आवश्यकता किस आधार पर महसूस हुई? क्या नई जांच के लिए कोई नया तथ्य या नया साक्ष्य सामने आया था? क्या पूर्व जांच की वैधता पर सक्षम प्राधिकारी ने कोई प्रश्न उठाया था? और क्या पुनः जांच के लिए विधिवत आदेश जारी किया गया था? विभागीय सूत्रों का दावा है कि निचले स्तर के कर्मचारियों के माध्यम से ऐसा जांच प्रतिवेदन तैयार कराने की कोशिश की जा रही थी, जिसके आधार पर जगदीश कुशवाहा की बहाली का रास्ता खुल सके,यह गंभीर आरोप है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि तथा संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना आवश्यक है।

एक ओर सेवा समाप्ति,दूसरी ओर पुनः पदस्थापना के आरोप-सूत्रों के अनुसार, जगदीश कुशवाहा को सेवा समाप्ति के बाद पुनः बैंक मुख्यालय में पदस्थ किए जाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, यदि सेवा समाप्ति के बाद पुनः पदस्थापना की गई है,तो उसके लिए जारी आदेश, सक्षम स्वीकृति और लागू सेवा नियमों की स्थिति सार्वजनिक होनी चाहिए,यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि जिस मामले में पहले जांच के आधार पर सेवा समाप्ति हुई,उसमें बाद में ऐसा कौन-सा नया तथ्य सामने आया, जिसके आधार पर बहाली या पुनः पदस्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ी? यदि जांच में पहले वित्तीय अनियमितता प्रमाणित हुई थी, तो बाद में उस निष्कर्ष को बदलने का आधार क्या था? और यदि पहले की जांच में त्रुटि थी,तो उस त्रुटि के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई? करोड़ों की शिकायतें कहां हैं? फाइलें टेबल पर हैं या धूल में? बैंक के सीईओ के विरुद्ध उठ रहे सवालों का एक बड़ा हिस्सा बैंक की अन्य शिकायतों से जुड़ा है,फसल बीमा से संबंधित लगभग 32 लाख रुपये की कथित अनियमितता,पशु ऋण वितरण में दो करोड़ रुपये से अधिक के कथित फर्जी ऋण,तथा विभिन्न शाखाओं और समितियों में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर शिकायतें और समाचार प्रकाशित होने की बात सामने आती रही है, इन मामलों में आरोपों की सत्यता और जिम्मेदारी जांच से ही तय होगी,लेकिन बैंक प्रबंधन को यह बताना चाहिए कि इन शिकायतों पर अब तक कितनी जांच हुई? कितने मामलों में जांच प्रतिवेदन तैयार हुआ? कितने मामलों में वसूली की गई? कितने कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई हुई? और कितने मामलों में शिकायतें अब भी लंबित हैं? यदि किसी मामले में वित्तीय अनियमितता प्रमाणित हुई है,तो संबंधित व्यक्ति को सेवा में बनाए रखने या पुनः पदस्थ करने का आधार क्या है? यदि मामला न्यायालय में लंबित है,तो बैंक ने न्यायालयीन स्थिति के अनुरूप क्या कदम उठाए हैं? यही वह हिसाब है,जिसे सार्वजनिक किए बिना बैंक प्रबंधन की निष्पक्षता पर उठ रहे सवाल समाप्त नहीं होंगे।

सीईओ की सफाई अपनी जगह, लेकिन बाकी शिकायतों का जवाब भी जरूरी-श्रीकांत चंद्राकर का यह कहना कि उनके विरुद्ध शिकायतें इसलिए हो रही हैं क्योंकि उन्होंने एक कर्मचारी के मामले में जांच कराई,उनका पक्ष है,लेकिन किसी एक मामले की जांच कर देना अपने आप में यह प्रमाणित नहीं करता कि बैंक में बाकी सभी शिकायतों पर भी निष्पक्ष और समान कार्रवाई हुई है, यदि सीईओ वास्तव में बैंक में अनियमितताओं के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं,तो उन्हें उन सभी लंबित शिकायतों की स्थिति भी सार्वजनिक करनी चाहिए, जिनमें करोड़ों रुपये की कथित वित्तीय गड़बड़ी के आरोप हैं,इससे यह स्पष्ट होगा कि जांच की प्रक्रिया किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है,बल्कि बैंक के सभी मामलों में समान रूप से लागू हो रही है,क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि किसकी फाइल खोली गई, सवाल यह भी है कि किसकी फाइल अब तक बंद पड़ी है और क्यों?

अब इन सवालों का जवाब कौन देगा?

1. वर्ष 2020 से 2026 तक बैंक की शाखाओं और समितियों में वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या कितनी है?
2. फसल बीमा से जुड़े लगभग 32 लाख रुपये की कथित अनियमितता के मामले में वर्तमान स्थिति क्या है?
3. पशु ऋण वितरण में दो करोड़ रुपये से अधिक के कथित फर्जी ऋण के मामले में जांच और कार्रवाई कहां तक पहुंची?
4. जगदीश कुशवाहा की सेवा समाप्ति के बाद पुनःजांच या बहाली की प्रक्रिया किस आदेश और किस नियम के तहत शुरू की गई?
5. पूर्व उच्च स्तरीय जांच के बाद पुनःजांच दल गठित करने का आधार क्या था?
6. जांच दल में शामिल कर्मचारियों ने जांच से इनकार किया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई किस आधार पर की गई?
7. निर्मला तिवारी से संबंधित जांच प्रतिवेदन के आधार पर अब तक क्या अंतिम विभागीय कार्रवाई हुई है?
8. पदमनी जैन के मामले में सेवा समाप्ति के बाद पुनःपदस्थापना संबंधी जांच निष्कर्ष पर क्या कार्रवाई की गई?
9. क्या बैंक की सभी लंबित शिकायतों की सूची और उनकी जांच की वर्तमान स्थिति सार्वजनिक की जाएगी?
10. क्या सीईओ स्वयं अपने कार्यकाल में लंबित शिकायतों और उन पर हुई कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा जारी करेंगे?

फाइलों की भी किस्मत होती है क्या?

बैंक की कहानी में सबसे दिलचस्प बात यही है कि एक तरफ 35 साल पुरानी नियुक्ति के दस्तावेजों को खोजकर उनके पन्ने पलटे जा रहे हैं,वहीं दूसरी तरफ पिछले छह वर्षों की वित्तीय शिकायतों पर कार्रवाई का हिसाब मांगना पड़ रहा है,किसी फाइल में नियुक्ति का आदेश नहीं मिलता,किसी में अनुमति नहीं मिलती,किसी में चालान का हिसाब अधूरा मिलता है, कहीं सेवा समाप्ति का आदेश अगले दिन पलट जाता है,तो कहीं पहले की जांच के बाद पुनः जांच की जरूरत पड़ जाती है,कहीं बहाली की चर्चा है,कहीं सेवा समाप्ति का सवाल है और कहीं करोड़ों की कथित अनियमितताओं की शिकायतें जवाब की प्रतीक्षा में हैं,ऐसे में आम खाताधारक का सवाल बिल्कुल सीधा है–बैंक में नियम सबके लिए समान हैं या फाइल देखकर नियमों की व्याख्या बदल जाती है? सीईओ साहब, 1990-91 की फाइल खोलना अच्छी बात है, लेकिन 2020 से 2026 तक की शिकायतों पर भी धूल झाड़िए,आखिर बैंक की पारदर्शिता का प्रमाण किसी एक कर्मचारी की जांच रिपोर्ट नहीं,बल्कि हर शिकायत पर निष्पक्ष और समान कार्रवाई है,फाइलों की दुनिया में किसी को जांच की रोशनी और किसी को इंतजार का अंधेरा मिले,तो सवाल उठेंगे ही,अब देखना यह है कि बैंक प्रबंधन इन सवालों का जवाब दस्तावेजों से देता है या फिर एक और फाइल जवाब की प्रतीक्षा में रख दी जाती है।

CMYK

रोमांचक मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी और नेपोली के बीच मैच ड्रॉ



मैनचेस्टर । मैनचेस्टर सिटी को एतिहाद स्टेडियम में यूईएफए चैंपियंस लीग के मुकाबले में नेपोली के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेलना पड़ा। रेयान चेर्की के 86वें मिनट में किए गए गोल से सिटी घर में हार से बच सकी। सिटी इस मैच में दो बार पिछड़ी, लेकिन दोनों बार वापसी करते हुए एक अंक हासिल किया। इस ड्रॉ से सिटी की हालिया खराब फॉर्म को लेकर चिंता कम नहीं हुई है। टीम ने सभी प्रतियोगिताओं में अपने पिछले सात मैचों में सिर्फ एक जीत हासिल की है। मेजबान टीम ने अटैकिंग अंदाज में शुरुआत की। इलियट एंडरसन ने शुरुआती दो मिनट में ही नेपोली के गोलकीपर वांजा मिलिंकोविक-सैविक को परखा। इसके बाद निकोओ 'रेली का हेडर क्रॉसबार के ऊपर चला गया। शुरुआती दबाव के बाद नेपोली ने धीरे-धीरे मैच में पकड़ बनाई। सिटी के पूर्व मिडफील्डर केविन डी ब्रुइन ने मेहमान टीम के अटैक को संभाला। हाफटाइम से ठीक पहले सैम बेउकेमा के हेडर को जियानलुइगी डोनारुम्मा ने शानदार सेव कर बचा लिया। 55वें मिनट में नेपोली ने बढ़त बना ली। रैसमस होजलुंड ने मार्क गुएही को पीछे छोड़ते हुए दमदार लो शॉट से डोनारुम्मा को छकाया। सिटी के कोच ने जेरेमी डोकू को मैदान में उतारा और इसका फौरन फायदा मिला। डोकू के बनाए मौके पर अय्यूब बौआदी ने 66वें मिनट में सिटी के लिए अपना पहला गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। हालांकि, 10 मिनट बाद ही नेपोली ने फिर बढ़त ले ली। लियोनार्डो स्पिनाजोला के क्रॉस पर नोआ लैंग ने शानदार वॉली मारी, जिस पर डोनारुम्मा के पास कोई मौका नहीं था। 79वें मिनट में जोस्को ग्वार्डिओल का शॉट वुडवर्क से टकरा गया, लेकिन आखिरकार 86वें मिनट में चेर्की ने शानदार फिनिश करते हुए सिटी को 2-2 की बराबरी दिला दी। देर से मिले गोल ने सिटी को घर में हार से तो बचा लिया, लेकिन शुरुआती दबदबे को जीत में न बदल पाना उनकी लगातार जारी मुश्किलों को दिखाता है।

सुपर 90: चौथा सीजन अगले माह, 12 दिनों तक रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे

नैरोबी । पूर्व इंटरनेशनल स्टार क्रिस गेल, शाकिब अल हसन, जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, तिलकरत्ने दिलशान, शॉन मार्श, फैबियन एलन और कार्लोस ब्रैथवेट 3 दिसंबर को केन्या के नैरोबी में शुरू होने वाले सुपर 90 सीजन 4 में मुख्य आकर्षण होंगे। टूर्नामेंट के चौथे एडिशन में कई जाने-माने इंटरनेशनल क्रिकेटरों वाली सात फ्रेंचाइजी एक साथ आएंगी, जिससे 12 दिनों तक रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे। इस कॉम्पिटिशन में 22 मैच होंगे। फाइनल 14 दिसंबर को होगा। वेस्टइंडीज के क्रिस गेल पंजाब टाइटन्स के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे, जबकि बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन लंदन जायंट्स के लिए खेलेंगे। इंग्लैंड के जेसन रॉय और एलेक्स हेल्स क्रमशः मेरू थंडर्स और नैरोबी लायंस की तरफ से खेलेंगे। श्रीलंका के पूर्व कप्तान तिलकरत्ने दिलशान भी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर शॉन मार्श के साथ टूर्नामेंट में अपना अनुभव लेकर आएंगे। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर फैबियन एलन और कार्लोस ब्रैथवेट इंटरनेशनल लाइनअप को और मजबूत करेंगे। टूर्नामेंट में कई और जाने-माने इंटरनेशनल नाम भी होंगे, जिनमें एविन लुईस, क्रिस लिन, इमाद वसीम, महमूदुल्लाह, वेन पार्नेल, रवि बोपारा, अंबाती रायुडू, मिशेल जॉनसन और समित पटेल शामिल हैं, जो हिस्सा लेने वाली टीमों में और गहराई और अनुभव जोड़ेंगे। शुरुआती मैच में पंजाब टाइटन्स का मुकाबला 3 दिसंबर को नैरोबी जिमखाना क्रिकेट क्लब में दिल्ली रॉयल्स से होगा। नैरोबी लायंस का मुकाबला 4 दिसंबर को लंदन जायंट्स से होगा, जबकि दिल्ली रॉयल्स उसी दिन बाद में हरियाणा वॉरियर्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी।लंदन जायंट्स का मुकाबला 5 दिसंबर को एल्डोरेट टाइगर्स से होगा, जबकि मेरू थंडर्स उसी दिन पंजाब टाइटन्स के खिलाफ अपने कैप्टेन की शुरुआत करेगी।

हेनरी बोले- डफी की स्किल पर कोई सवाल नहीं

नई दिल्ली । भारत के साथ वेलिंगटन में खेले गए पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी पूरी तरह प्रभावहीन रहे थे। डफी ने 33 ओवर में 201 रन लुटाकर महज 1 विकेट लिया था। इस प्रदर्शन के बाद आलोचना का शिकार हुए डफी को टीम के सीनियर तेज गेंदबाज मैट हेनरी का समर्थन मिला है। मैट हेनरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'जैकब डफी एक 'क्लासी बॉलर' हैं। उन्होंने इतने सालों में दिखाया है कि वह पूरी तरह से टीम के बारे में सोचते हैं। जब हम सुझाव देते हैं कि शायद हम यहां एक प्लान बनाएं, तो वह अपने निजी आंकड़ों के बारे में चिंतित नहीं होते।' हेनरी ने कहा, 'डफी की स्किल पर कोई सवाल नहीं है। हमारे लिए, ऐसे पल थे जब हमें किसी ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो एक अलग प्लान आजमा सके, और वह ऐसा करने के लिए तैयार था। मुझे लगता है कि शायद यही टीम की क्वालिटी है। यह नतीजे की चिंता नहीं है, बल्कि यह है कि आप गेम पर कैसे असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में यह दिखा है, उसके ऐसे माइंडसेट की वजह से उसके असर मैच जिताने वाले रहे हैं। इसलिए हम उसे लेकर ज्यादा परेशान नहीं हैं।'



उन्होंने कहा कि बेसिन रिजर्व पर गेंद बहुत कम स्लिप तक जा पाती थी। इस वजह से डफी को आंकड़ों की परवाह किए बिना बाउंसर फेंकने के लिए कहा गया था और उन्होंने यही किया। जैकब डफी का नाम न्यूजीलैंड के लिए तीनों फॉर्मेट के बेहतरीन गेंदबाजों के तौर पर लिया जाता है। दाएं हाथ का मध्यम गति का यह तेज गेंदबाज 5 टेस्ट में 26, 27 वनडे में 49 और 52 टी20 में 67 विकेट ले चुका है। न्यूजीलैंड को क्राइस्टचर्च में भारत के खिलाफ होने वाले दूसरे टेस्ट में डफी से वेलिंगटन वाले प्रदर्शन को भुलाकर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।

वैभव सूर्यवंशी के तूफानी दोहरे शतक की दुनियाभर में चर्चा, हिल गई रिकार्ड बुक

नई दिल्ली । 15 वर्षीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के तूफानी 'दोहरे शतक' की मदद से भारत-ए ने मंगलवार को यूएई के खिलाफ 7 विकेट से दमदार जीत दर्ज की। इस दौरान वैभव ने लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक, सबसे तेज 150 रन और सबसे तेज दोहरे शतक के साथ सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूएई की टीम ने हरप्रीत सिंह भाटिया (130) की शतकीय पारी की मदद से 8 विकेट खोकर 249 रन बनाए थे। इस पारी में अरशद खान ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए। इसके बाद वैभव ने तूफानी पारी खेलकर भारतीय टीम को महज 14.2 ओवरों में जीत दिला दी। यूएई के खिलाफ महज 28 गेंदों में शतक जड़कर वैभव सूर्यवंशी लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। मंगलवार को यूनिवर्सिटी ऑफ दोहा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्राउंड पर खेले गए मुकाबले में वैभव ने 53 गेंदों में 7 चौकों और 28 छक्कों के साथ 204 रन कूटे। इसी के साथ वैभव ने साउथ अफ्रीका के जेक फ्रेजर-मैकगर्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने साल 2023 में तस्मानिया के खिलाफ 29 गेंदों में शतक पूरा किया था। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका के दिग्गज एबी डिविलियर्स हैं, जिन्होंने साल 2015 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध 31 गेंदों में यह कारनामा किया था। बिहार की तरफ से खेलते हुए सकीबुल गनी ने साल 2025 में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 32 गेंदों में शतक पूरा किया था।

यह मुकाबला विजय हजारे ट्रॉफी में खेला गया था। वहीं, ईशान किशन इस लिस्ट में पांचवें पायदान पर हैं, जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में झारखंड के कप्तान के तौर पर महज 33 गेंदों में कर्नाटक के विरुद्ध शतक पूरा किया था।



यूएई के खिलाफ मुकाबले के दौरान वैभव ने सातवें ओवर की सभी गेंदों पर बाउंड्री लगाई। इस दौरान 6, 4, 4, 6, 6, 4 के साथ कुल 30 रन कूट दिए।इसके बाद वैभव ने महज 40 गेंदों में सबसे तेज 150 रनों का आंकड़ा छुआ। लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में वैभव ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले, उन्होंने साल 2025 में बिहार की तरफ से खेलते हुए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 59 गेंदों में यह कारनामा किया था। इस लिस्ट में एबी डिविलियर्स तीसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने 64 गेंदों (साउथ अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज, 2015) में ऐसा किया था।

वैभव की रिकार्ड पारी में युवराज की बड़ी भूमिका

नई दिल्ली । एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट के दौरान मंगलवार को इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ऐतिहासिक पारी खेली। यूएई ए के खिलाफ वैभव ने मात्र 53 गेंदों पर 28 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 204 रन की पारी खेली। इस दौरान वैभव ने 28 गेंदों पर शतक और 52 गेंदों पर दोहरा शतक लगाया। वैभव द्वारा लगाया गया लिस्ट ए इतिहास का यह सबसे तेज शतक और दोहरा शतक है। वैभव ने इस ऐतिहासिक पारी को खेलने के बाद बीसीसीआई टीवी से बात करते हुए कहा कि पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह से हुई आधे घंटे की बातचीत ने यूएई के खिलाफ मैच से पहले उनका आत्मविश्वास बढ़ाया। सूर्यवंशी ने कहा, 'मैंने कल सिर्फ चार लोगों से बात की। इसमें मेरे पिता, मेरे बचपन के कोच मनीष ओझा, मेरे अंडर-19 के दोस्त प्रथम जाचक और युवराज सिंह थे। युवराज सिंह से मैंने लगभग आधे घंटे तक बात की। उन्होंने मुझे मेरी बैटिंग के बारे में काफी कुछ समझाया। मैं काफी परेशान था।' उन्होंने कहा, 'मैं जब बैटिंग करने जाता था, तो मुझे जो दिक्कतें आ रही थीं, उनके बारे में मैंने उनसे खुलकर बात की। उन्होंने मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं 20 बॉल खेलता, तो स्कोर अलग होता। उन्होंने मुझे कुछ तकनीकी बातें भी समझाईं, जिससे मुझे बहुत मदद मिली।'

आईसीसी टेस्ट रैंकिंग...ब्रुक और रूट की बादशाहत बरकरार



भारतीय कप्तान शुभमन गिल और भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को बड़ा फायदा

नई दिल्ली । आईसीसी ने टेस्ट बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग बुधवार को जारी की। बल्लेबाजों की रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा, भारतीय कप्तान शुभमन गिल और भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को बड़ा फायदा हुआ है। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक पहले, इंग्लैंड के कप्तान जो रूट दूसरे स्थान पर हैं। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा को एक स्थान का फायदा हुआ है। वह तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को एक स्थान का घाटा हुआ है। हेड चौथे स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ पांचवें स्थान पर हैं। भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक स्थान की छलांग के साथ छठे और भारतीय कप्तान शुभमन गिल तीन स्थान की छलांग के साथ सातवें स्थान पर हैं।

न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र को 2 स्थान का नुकसान हुआ है। वह आठवें स्थान पर हैं। भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 5 स्थान की छलांग के साथ नौवें और अफगानिस्तान के कप्तान रहमत शाह 2 स्थान के नुकसान के साथ दसवें स्थान पर हैं।



दक्षिण अफ्रीका के रयान रिकेल्टन 10 स्थान की छलांग के साथ 16वें और न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स 13 स्थान की छलांग लगाते हुए 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं।शीर्ष 10 गेंदबाजों की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क पहले स्थान पर, भारत के जसप्रीत बुमराह तीन स्थान की छलांग लगाते हुए दूसरे, इंग्लैंड के ओली रॉबिनसन दो स्थान की छलांग लगाते हुए तीसरे स्थान पर हैं। दक्षिण अफ्रीका के मार्को जानसेन और न्यूजीलैंड के मैट हेनरी को दो-दो स्थान का नुकसान हुआ है। दोनों क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। दक्षिण अफ्रीका के कगिसो रबाडा दो स्थान की छलांग लगाते हुए छठे, दक्षिण अफ्रीका के सिमरोन हार्मर सातवें, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट बोलैंड दो स्थान के नुकसान के साथ आठवें, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस नौवें और ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड दसवें स्थान पर हैं।

वॉर्नर ने भी कराया रजिस्ट्रेशन

आईपीएल: नीलामी में दिखेगा 'जूनियर सहवाग' का जलवा!

मुंबई, एजेंसी। भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक बड़ी और रोमांचक खबर सामने आई है। इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन यानी 2027 में एक बार फिर 'सहवाग' सरनेम की गूंज सुनाई दे सकती है। पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने आखिरी बार साल 2015 में पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल खेला था। अब करीब 12 साल बाद उनके बेटे आर्यवीर सहवाग ने आईपीएल 2027 प्लेयर ऑक्शन की सूची में अपना नाम रजिस्टर कराकर फैंस की उम्मीदें जगा दी हैं। हालांकि, इस लिस्ट में एक चौंकाने वाला नाम गायब है। पूर्व कप्तान और कोच राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ ने इस साल नीलामी में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है।

अंडर-19 एशिया कप में शानदार प्रदर्शन का मिला इनाम

आर्यवीर सहवाग ने अपने करियर में पहली बार आईपीएल ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। हाल ही में संपन्न हुए अंडर-19 एशिया कप 2026 में उनके धमाकेदार प्रदर्शन ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया था। दोहा में खेले गए रोमांचक फाइनल में भारत की अंडर-19 टीम ने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को एक विकेट से हराकर खिताब जीता था। इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी के लिए आर्यवीर को 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया था।

गोवा में सजेगा बाजार, दांव पर होंगे 296 करोड़ रुपये

आईपीएल 2027 का प्लेयर ऑक्शन आगामी 16 दिसंबर को गोवा में आयोजित किया जाएगा। नीलामी के लिए कुल 1220 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस सूची में 939 भारतीय और 17 देशों के 281 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं, फ्रेंचाइजी के पास खर्च करने के लिए करीब 296 करोड़ रुपये का पर्स उपलब्ध होगा। युवा प्रतिभाओं के साथ-साथ दुनिया भर के कई दिग्गज क्रिकेटरों ने भी इस नीलामी के लिए अपना नाम भेजा है। हालांकि, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बाद अब 1220 खिलाड़ियों में से गिने चुने या यूं कहें 300 से 500 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, जो 16 दिसंबर को होने वाले ऑक्शन में उतरेंगे।



बेन स्टोक्स और डेविड वॉर्नर की 2 करोड़ के ब्रैकेट में वापसी

अंतरराष्ट्रीय सितारों की बात करें तो इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर बेन स्टोक्स और ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने 2 करोड़ रुपये के उच्चतम बेस प्राइस में खुद को रजिस्टर किया है। 35 वर्षीय स्टोक्स ने इस साल की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और वह आखिरी बार 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स (ष्टस्च) के लिए आईपीएल खेले थे। अब तक के अपने आईपीएल करियर में स्टोक्स ने राइजिंग पुणे सुपरजाएंट्स, राजस्थान रॉयल्स और सीएसके के लिए 45 मैचों में 935 रन बनाए हैं और 28 विकेट झटके हैं। भारतीय खिलाड़ियों में तेज गेंदबाज आवेश खान और दीपक चाहर ने भी खुद को दो करोड़ के शीर्ष ब्रैकेट में रखा है।

ईशांत शर्मा और नीतीश राणा भी अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची मेंनीलामी के लिए जारी अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और बल्लेबाज नीतीश राणा के नाम भी शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों भारतीय टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं और आईपीएल में 100 से ज्यादा मैचों का अनुभव रखते हैं। आईपीएल के नियमों के मुताबिक, अगर किसी भारतीय खिलाड़ी ने पिछले पांच साल में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है तो उसे नीलामी में अनकैप्ड खिलाड़ी की श्रेणी में रखा जाता है।इसी नियम के कारण ईशांत और नीतीश को अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में जगह मिली है। दोनों खिलाड़ियों का बेस प्राइस 50 लाख रुपये रखा गया है। इनके अलावा भारत के मनदीप सिंह, मयंक मार्कंडेय, नवदीप सैनी और चेतन सकारिया भी अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में शामिल हैं।

बोलैंड-रिचर्डसन ने कराया रजिस्ट्रेशन

आईपीएल 2027 की नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड और झाय रिचर्डसन ने भी अपना नाम दर्ज कराया है, हालांकि दोनों की उपलब्धता सीमित रहने वाली है। बोलैंड ने 2016 में आईपीएल के सिर्फ दो मैच खेले थे। उनका बेस प्राइस एक करोड़ रुपये है, लेकिन माना जा रहा है कि वह इस सीजन में उपलब्ध नहीं रहेंगे। वहीं, रिचर्डसन को पंजाब किंग्स ने 2021 सीजन से पहले 14 करोड़ रुपये में खरीदा था। उन्होंने अधिकतम दो करोड़ रुपये के बेस प्राइस पर नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि, वह पूरे सीजन के बजाय सिर्फ आधे टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध रहेंगे। रिचर्डसन ऑस्ट्रेलिया के लिए तीनों प्रारूपों में खेल चुके हैं। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बेवॉन-जॉन जैकब्स ने भी नीलामी के लिए अपना नाम दिया है, लेकिन वह टूर्नामेंट के सिर्फ 10 प्रतिशत हिस्से के लिए उपलब्ध रहेंगे। वहीं, इंग्लैंड के सैम बिलिंग्स 80 प्रतिशत लीग के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। वहीं, मिचेल स्टार्क ने आईपीएल 2027 के लिए अपना नाम उपलब्ध नहीं कराया है। ऑस्ट्रेलिया के ही ट्रेविस हेड भी इस सीजन की नीलामी के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

अन्य युवा सितारे भी ऑक्शन के मैदान में

आर्यवीर अकेले अंडर-19 स्टार नहीं हैं जो इस नीलामी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल जीत के हीरो रहे मोहित उत्वा ने भी ऑक्शन के लिए अपना नाम दिया है। इसके अलावा अंडर-19 टीम के अन्य प्रमुख खिलाड़ी काव्य पटेल और मनल चौहान भी नीलामी में उतरेंगे। इन सभी युवा भारतीय खिलाड़ियों का बेस प्राइस 30 लाख रुपये रखा गया है। दूसरी तरफ, अंडर-19 टीम के कप्तान लक्ष्य रायचंदानी और अन्वय द्रविड़ ने खुद को इस ऑक्शन से अलग रखा है।

शतरंज विश्व चैंपियनशिप



समय के दबाव में भी डटे रहे गुकेश, सिंदारोव के साथ पहला मैच ड्रॉ, 38 चालों तक चली जंग

जिनेवा। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2026 की शुरुआत भारतीय ग्रैंडमास्टर और मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश ने ड्रॉ के साथ की। चैंपियनशिप के पहले मुकाबले में उन्होंने उज्बेकिस्तान के ग्रैंडमास्टर जावोखिर सिंदारोव को बराबरी पर रोक दिया। सफेद मोहरों से खेल रहे सिंदारोव के खिलाफ गुकेश ने काले मोहरों से मुकाबला किया। दोनों खिलाड़ियों के बीच यह मुकाबला 38 चालों तक चला और तीन बार एक जैसी स्थिति बनने के बाद ड्रॉ पर समाप्त हुआ।

मुकाबले में गुकेश ने रुई लोपेज-बर्लिन डिफेंस का सहारा लिया। सिंदारोव इस ओपनिंग के लिए अच्छी तैयारी के साथ उतरे थे। उन्होंने तेजी से चालें चलीं और बर्लिन डिफेंस की एक अलग रणनीति अपनाई। उनकी तैयारी साल 2020 में ग्रैंडमास्टर फैबियानो कारुआना और वेस्ली सो के बीच खेले गए मुकाबले पर आधारित थी, जिसमें कारुआना ने सफेद मोहरों से जीत हासिल की थी।

हालांकि, गुकेश ने अपनी चालों से मुकाबले को संतुलित बनाए रखने की कोशिश की। सिंदारोव की 13वीं चाल एनई4 के जवाब में गुकेश ने बीडी7 खेला। इसके बाद सिंदारोव ने 14वीं चाल में सी4 खेली, जिस पर गुकेश ने ए5 से जवाब दिया। मुकाबले के दौरान गुकेश को समय के दबाव का सामना करना पड़ा। 17वीं चाल पर सिंदारोव के बी3 खेलने के बाद गुकेश ने बीबी4 की चाल चली। इस चाल से उन्होंने डी2 पर मौजूद सफेद खिलाड़ी के रूक को निशाना बनाया। इस चाल को चलने में गुकेश ने करीब 36 मिनट लगाए।

इसके बाद 22वीं चाल पर सिंदारोव ने 20 मिनट सोचने के बाद एनई1 खेला। दोनों खिलाड़ियों के बीच इसके बाद कई मोहरों की अदला-बदली हुई। आखिरकार मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इस दौरान सिंदारोव को गलत तरीके से ड्रॉ का दावा करने के कारण घड़ी पर समय का जुर्माना भी झेलना पड़ा।

बीजापुर के जंगल में नक्सलियों के दफन मिले 39.77 लाख

डिब्बे में थी 500-500 की गड्डियां,13 लाख की इनामी 2 नक्सलियों ने भी किया सरेंडर

बीजापुर,25 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को नक्सली डम्प से बड़ी मात्रा में कैश मिला है। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के बड़ेपल्ली गांव के जंगल में जमीन के नीचे छिपाकर रखे गए 39 लाख 77 हजार रुपए बरामद किए गए हैं। रकम 500-500 रुपए के नोटों में थी। पुलिस के मुताबिक, इससे पहले भी जिले में अलग-अलग कार्रवाई के दौरान नक्सली डम्प से 7 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा कैश और 8.5 किलो सोना बरामद किया जा चुका है। ओडिशा में सक्रिय 13 लाख की इनामी महिला समेत 2 नक्सलियों ने बीजापुर में सरेंडर भी किया है। महिला 20 साल से संगठन में सक्रिय थी। कई मुठभेड़ों में शामिल होने का आरोप है।

मुखबिर की सूचना पर जंगल में सर्चिंग

पुलिस के मुताबिक, 24 नवंबर को सूचना मिली थी कि बड़ेपल्ली के जंगल में जमीन के अंदर संदिग्ध सामान छिपाकर रखा गया है। इसके बाद एसपी उमेश प्रसाद गुप्ता के निर्देश पर डीआरजी, भैरमगढ़ थाना पुलिस और बीडीएस की संयुक्त टीम ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया।



जमीन के अंदर बोरी में मिला स्टील का डिब्बा

सर्चिंग के दौरान बीडीएस टीम ने डिमाइनिंग और तलाशी की कार्रवाई की। इस दौरान जमीन के अंदर बोरी में छिपाकर रखा गया स्टील का डिब्बा मिला। डिब्बे में टेप से लिपटे पैकेट रखे थे। जांच करने पर पैकेटों से 500-500 रुपए के नोटों में कुल 39 लाख 77 हजार रुपए मिले।

पहले 7.60 करोड़ कैश और 8.5 किलो सोना मिला

पुलिस के अनुसार, बीजापुर में इससे पहले भी माओवादी डम्प से बड़ी मात्रा में नकदी और सोना बरामद किया जा चुका है। अब तक की अलग-अलग कार्रवाइयों में 7 करोड़ 60 लाख 33 हजार 800 रुपए नकद और 8.5 किलोग्राम सोना मिल चुका है।

रकम कहां से आई,जांच का विषय

बड़ेपल्ली के जंगल से मिली ताजा रकम को भी माओवादी डम्प की बरामदगी में जोड़ा गया है। इतनी बड़ी नकदी और सोना कहां से जुटाया गया था और इसका इस्तेमाल किन गतिविधियों के लिए होना था, इसकी जांच की जा रही है।

13 लाख की इनामी महिला समेत 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर

ओडिशा में सक्रिय एक महिला समेत दो नक्सली कैडरों ने बुधवार 25 नवंबर को बीजापुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। दोनों पर कुल 13 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वालों में नागमणि कुड़मे उर्फ शीला (32) और गंगा सोढ़ी उर्फ सोनू (26) शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक,नागमणि संगठन में CyPCM और गंगा ACM रैंक पर सक्रिय था।

पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर छोड़ा संगठन : पुलिस के अनुसार,छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति,सुरक्षा बलों के अभियान और पुनर्वास कार्यक्रमों से प्रभावित होकर दोनों ने मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। जिला पुलिस,डीआरजी,कोबरा और CRPF के संयुक्त प्रयासों से दोनों का आत्मसमर्पण कराया गया।

2006 से माओवादी संगठन में सक्रिय थी नागमणि : पुलिस ने बताया कि नागमणि मूल रूप से बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र के चिपुरभट्टी की रहने वाली है। वह 2006 से माओवादी संगठन में सक्रिय थी। 2006-07 में गांधी ताती उर्फ हरबू के जरिए PLGA सदस्य के रूप में संगठन में शामिल हुई थी।

2021 में ओडिशा की कंपनी नंबर 08 में मिली जिम्मेदारी

पुलिस के मुताबिक,नागमणि को 2009 में ACM और 2016 में DVCM बनाया गया। इसके बाद 2021 में उसे ओडिशा राज्य की कंपनी नंबर 08 में CyPCM पद पर जिम्मेदारी दी गई। वह छत्तीसगढ़ और ओडिशा में नक्सल गतिविधियों में सक्रिय रही।

कई मुठभेड़ों में शामिल होने का आरोप

पुलिस के अनुसार,नागमणि 2011 में तिमापुर-चिंतलनार क्षेत्र की घटना, 2022 में ओडिशा के दड़ाईपानी और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के ओड़ क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में शामिल रही है। इसके अलावा 2024 में ओडिशा के कंधमाल जिले के पाडेल क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में भी उसकी संलिप्तता बताई गई है।

छत्तीसगढ़ में मखाना की खेती बढ़ाने वर्कशॉप

4 राज्यों के 300 किसान जुटेंगे,अभी राज्य में 133.86 हेक्टेयर में हो रही मखाने की खेती

रायपुर,25 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ में गुरुवार से मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू होगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में होने वाली इस कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के अलावा मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और ओडिशा के करीब 300 किसान और महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्य शामिल होंगे। कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल सुबह 11 बजे इसका शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में फिलहाल 133.86 हेक्टेयर में मखाने की खेती हो रही है। इसमें 96.43 हेक्टेयर तालाबों और 37.42 हेक्टेयर कम गहरे पानी वाले खेतों में है। कार्यशाला में किसानों को मखाने की उन्नत खेती,प्रोसेसिंग, मशीनों के इस्तेमाल,कीट-रोग नियंत्रण और मार्केटिंग की जानकारी दी जाएगी। साथ ही मखाना उत्पादों और प्रोसेसिंग तकनीक की प्रदर्शनी भी लगेगी।



6 जिलों में हो रही मखाने की खेती : प्रदेश में धमतरी, रायपुर के आरंग,बालोद, महासमुंद, गरियाबंद और जांजगीर-चांपा प्रमुख मखाना उत्पादक जिले हैं। यहां 15 हेक्टेयर में मखाना बीज उत्पादन का कार्यक्रम भी चल रहा है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड में छत्तीसगढ़ को शामिल किए जाने के बाद राज्य में इसकी खेती बढ़ाने की संभावनाएं बनी हैं।

खेती से लेकर मार्केटिंग तक की जानकारी देंगे विशेषज्ञ: कार्यशाला में राष्ट्रीय मखाना संस्थान, बिहार और लुधियाना के विशेषज्ञों के साथ कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक किसानों को जानकारी देंगे। इसमें डॉ. मनोज कुमार, धर्मेंद्र कुमार, डॉ. विद्यानंद झा, डॉ. राजेश कुमार विश्वकर्मा, डॉ. घनश्याम दास साहू और डॉ. गजेंद्र चंद्राकर शामिल होंगे।

मखाना उत्पादन बढ़ाने के लिए बोर्ड से मिल रही मदद : राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की ओर से खेती का रकबा बढ़ाने,बीज उत्पादन,फसल कटाई के बाद प्रबंधन,प्रोसेसिंग,मार्केटिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए अनुदान और दूसरी तरह की सहायता दी जा रही है। कार्यशाला में किसानों और उद्यमियों को इन योजनाओं और नई तकनीकों की जानकारी भी दी जाएगी।

सुकमा के जंगल में नक्सलियों का मिला डंप...8 देसी हथियार और 229 जिंदा कारतूस समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद

सुकमा,25 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने दुर्गम जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए डम्प का पता लगाकर भारी मात्रा में हथियार,कारतूस,विस्फोटक और अन्य नक्सली सामग्री बरामद की है। बरामद सामग्री में 8 कंट्रीमेड हथियार,विभिन्न हथियारों के 229 जिंदा कारतूस,एक टिफिन आईईडी, हैंड ग्रेनेड और इलेक्ट्रिक डेटोनेटर शामिल हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आत्मसमर्पित नक्सलियों से प्राप्त महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस के आधार पर 25 नवंबर को थाना चिंतलनार क्षेत्र के गुण्डराजगुड़ेम और रासापल्ली के जंगल-पहाड़ी इलाके में सर्चिंग एवं एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज बद्री नारायण मीणा,पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज तिर्की एवं मनीष कुंवर के मार्गदर्शन में जिला बल, डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। अभियान के दौरान रासापल्ली के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा पहले से छिपाकर रखा गया डम्प मिला। इसकी तलाशी लेने पर 2 सिंगल शॉट रायफल और 6 भरमार बंदूक सहित कुल 8 देसी हथियार बरामद किए गए। इसके अलावा एके-47 के 98, एसएलआर के 49, इंसास के 35, .303 के 30,9 एमएम के 13 और 12 बोर के 4 जिंदा कारतूस मिले। इस तरह कुल 229 कारतूस बरामद किए गए।



सर्चिंग के दौरान मिली ये सामग्रियां

सर्चिंग के दौरान 10 से 12 किलोग्राम वजन का एक टिफिन आईईडी भी मिला,जो वायर रहित अवस्था में था। इसके साथ 3 हैंड ग्रेनेड, 4 देशी तीर बम,10 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, बीजीएल सेल,बीजीएल कारतूस, लगभग 50 मीटर कोडेक्स वायर और करीब 5 किलोग्राम गन पाउडर भी बरामद किया गया। संयुक्त टीम को मौके से एके-47 और इंसास की 4-4 मैगजीन, स्टेन गन की 2 मैगजीन,वायरलेस सेट,बैटरियां,रिमोट रिसीवर,इलेक्ट्रिक वायर,नक्सली साहित्य,काली वर्दी के 15 जोड़ी सेट,कॉम्बैट वर्दी का कपड़ा,दवाइयां और अन्य उपयोगी सामग्री भी मिली है।

नक्सल डंप की तलाश में लगातार अभियान

पुलिस के मुताबिक,जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत जंगलों और दुर्गम इलाकों में छिपाकर रखे गए हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री के डम्प की तलाश लगातार की जा रही है। बरामद सामग्री को सुरक्षित कब्जे में लेकर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुकमा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में शांति,सुरक्षा और विकास का माहौल बनाए रखने के लिए सर्चिंग एवं एरिया डोमिनेशन अभियान आगे भी जारी रहेगा।

नारायणपुर में भी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद

नारायणपुर में भी पुलिस ने नक्सलियों के डंप का पता लगाया और एक नग स्नक एक नग इंसास रायफल समेत भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की। डंप से ऑटोमेटिक एसएलआर व इंसास हथियारों के 52-52 नग जिंदा कारतूस,वायरलेस सेट 2 नग, लेजर पेन,मैगजीन कवर,देशी कट्टा भी बरामद किया गया। नक्सलवाद के खात्मे के साथ जिले में नक्सलियों के डम्प की सर्चिंग जारी है।

दीपक और बरखा टंडन ठगी मामला : पुलिस को मिले अहम सबूत

पुलिस कमिश्नर ने कहा-कई रसूखदारों को जारी हो सकता है नोटिस

रायपुर,25 नवम्बर 2026। ठगी और धोखाधड़ी के आरोपों में घिरे दीपक टंडन और बरखा टंडन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। तेलीबांधा थाने में दर्ज मामलों को लेकर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में आरोपी दंपत्ति ने कई अहम खुलासे किए हैं। वहीं, जांच के दौरान पुलिस के हाथ कई महत्वपूर्ण सबूत भी लगे हैं। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ठगी और धोखाधड़ी से जुड़े प्रकरणों में पुलिस ने साक्ष्य जुटाए हैं। आरोपियों से पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर तेलीबांधा पुलिस कुछ रसूखदार लोगों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। पुलिस कमिश्नर ने बताया,पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ठगी के इस पूरे मामले में किन-किन लोगों की भूमिका रही है और आरोपियों के साथ उनका क्या संबंध था। फिलहाल आरोपी दीपक और बरखा टंडन को 28 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। आने वाले दिनों में इस प्रकरण में कुछ और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।



न्यूज पोर्टल की आड़ में ब्लैकमेलिंग का आरोप : पुलिस के मुताबिक,दीपक टंडन पर न्यूज पोर्टल की आड़ में लोगों की छवि खराब करने वाली भ्रामक खबरें प्रकाशित करने का आरोप है। आरोप है कि वह AI टूल की मदद से लोगों की तस्वीरों में छेड़छाड़ कर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री तैयार करता था। इसके बाद ऐसी तस्वीरें और भ्रामक खबरें प्रसारित कर संबंधित लोगों से रुपये वसूलने के लिए दबाव बनाया जाता था। इस मामले में तिफरा निवासी मणिशंकर पांडेय की शिकायत पर सिरगिट्टी थाने में अपराध दर्ज किया गया था।

6 नवंबर को रायपुर से हुई थी गिरफ्तारी

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने 6 नवंबर को रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर स्थित रजत प्राइम अपार्टमेंट से दीपक टंडन को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो मोबाइल फोन भी जब्त किए थे। पुलिस का दावा है कि मोबाइल की जांच में आपत्तिजनक फोटो, वीडियो और ऑडियो सामग्री मिली है।

दीपक टंडन को होटल 'वेलकम श्री' पहुंची पुलिस : रिमांड मिलते ही रविवार की रात तेलीबांधा थाना क्षेत्र में दर्ज पांच एफआईआर की जांच के सिलसिले में पुलिस की टीम आरोपी दीपक उर्फ अंबेडकर टंडन को लेकर उसके होटल 'वेलकम श्री' पहुंची। होटल में सामने आए नए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने विभिन्न कमरों और अंदर संचालित स्पा सेंटर की जांच की। इस दौरान स्पा सेंटर से शराब की बोतलें,सिगरेट, ग्राहकों की डायरी,मोबाइल नंबर और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए।

होटल के स्पा सेंटर का वीडियो आया सामने : महाठग दीपक टंडन के होटल के अंदर संचालित स्पा सेंटर का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दीपक टंडन दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि इसी होटल में दीपक कई लोगों को ठहराता था। आरोप है कि यहां लोगों के आपत्तिजनक वीडियो और फोटो बनाए जाते थे। हालांकि, इस संबंध में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

जमीन और गाड़ियों के दस्तावेज बरामद : जांच कार्रवाई को लेकर एसीपी रमाकांत साहू ने बताया था कि होटल वेलकम श्री की पूरी तलाशी ली गई है। इस दौरान कुछ जमीन से जुड़े दस्तावेज, डायरी और गाड़ियों के कागजात बरामद हुए हैं।

कोयला लेवी घोटाला : आईएएस जयप्रकाश मौर्य ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में लगाई याचिका

बिलासपुर,25 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला लेवी घोटाले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी जयप्रकाश मौर्य की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से पेश छठे पूरक चालान में नाम शामिल किए जाने के बाद अधिकारी ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोयला परिवहन के नाम पर कथित अवैध वसूली के मामले की जांच लंबे समय से जारी है। इस घोटाले में पूर्व कलेक्टर रानू साहू, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी और पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी समेत कई लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच की जा रही है। अब इस मामले की जांच की आंच तत्कालीन खनिज संचालक रहे आईएएस अधिकारी जयप्रकाश मौर्य तक पहुंच गई है। जांच एजेंसी ने 5 अक्टूबर 2026 को विशेष अदालत में पेश किए गए छठे पूरक चालान में जयप्रकाश मौर्य का नाम शामिल किया है। एजेंसी का आरोप है कि जब्त डायरियों में दर्ज कथित लेनदेन के अनुसार,मौर्य ने घोटाले के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी से करीब एक करोड़ रुपये नगद प्राप्त किए थे।



कोयला परिवहन में अवैध वसूली का आरोप

जांच एजेंसी के मुताबिक,कोयला परिवहन पर 25 रुपये प्रति टन और आयरन पैलेट के परिवहन पर 100 रुपये प्रति टन की दर से अवैध वसूली की व्यवस्था बनाई गई थी। आरोप है कि इस व्यवस्था को लागू कराने और संचालित करने में जयप्रकाश मौर्य की भूमिका रही। इसके अलावा जुलाई 2020 में ऑनलाइन ई-परमिट जारी करने से पहले जिला खनिज अधिकारी की मंजूरी अनिवार्य करने और जनवरी 2022 में ट्रांजिट पास व्यवस्था लागू करने के फैसले भी जांच के दायरे में हैं। फिलहाल,अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के रुख और शासन के जवाब का इंतजार है। मामले में जांच एजेंसी के आरोपों पर अंतिम न्यायिक फैसला आना अभी बाकी है।

कांग्रेस नेता उमेश रगड़े पर कारोबारी को धमकाने का केस

गाली-गलौज का ऑडियो वायरल,भतीजे के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट वापस लेने का दबाव

रायपुर,25 नवम्बर 2026। कारोबारी से मारपीट के मामले में रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में कांग्रेस नेता उमेश रगड़े के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कारोबारी विजय जेठानी का आरोप है कि 22 नवंबर को उनके पास एक अनजान नंबर से फोन आया था। फोन करने वाले ने खुद को उमेश रगड़े बताया और भतीजे गोलू रगड़े व अतुल तलमेल के खिलाफ दर्ज मारपीट की रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाया। मना करने पर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। यह मामला आजाद चौक थाना क्षेत्र का है। कारोबारी के मुताबिक, उन्होंने 21 नवंबर को गोलू रगड़े उर्फ शंका और अतुल तलमेल के खिलाफ आजाद चौक थाने में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके अगले दिन 22 नवंबर को दोपहर 12:56 बजे उनके मोबाइल पर फोन आया। फोन करने वाले ने रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाया। मना करने पर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद कारोबारी ने 24 नवंबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और 351(4) के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायत में फोन करने वाले की पहचान अज्ञात नंबर के धारक के रूप में दर्ज है। कारोबारी ने आरोप लगाया है कि फोन करने वाले ने अपना नाम उमेश रगड़े बताया था।

पेंड्रावन जलाशय विवाद : भूपेश बघेल की सरकार को दो टूक,कहा...वापस लें अनुमति,नहीं तो कांग्रेस करेगी आंदोलन

रायपुर,25 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ में पेंड्रावन-बंगोली जलाशय में खनन को लेकर लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को एक्टिविस्ट आलोक शुक्ला के साथ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने सरकार को दो टूक चेतावनी दी है कि सरकार लीज अनुमति वापस नहीं लेती है, तो कांग्रेस आंदोलन करेगी।

यह सरकार का किसान विरोधी रवैया : कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पेंड्रावन जलाशय क्षेत्र में खनन की अनुमति न कांग्रेस सरकार और न रमन सिंह सरकार ने दिए, लेकिन वर्तमान सरकार ने खदान को लीज पर दे दिया। यह सरकार का किसान विरोधी रवैया है।



किसानों के साथ आंदोलन की चेतावनी : उन्होंने कहा कि पेंड्रावन जलाशय क्षेत्र को लेकर जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट में जलाशय और बांध को नुकसान होने की बात कही गई थी। स्थानीय ग्रामीण ने भी लीज रद्द करने की मांग की। सरकार अगर यह लीज वापस नहीं लेती है तो कांग्रेस इसे लेकर किसानों के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। वहीं विधानसभा में इस मामले को उठाया जाएगा।

किसानों के साथ ये सरकार का मजाक : मौसम की मार और धान खरीदी में किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर भी भूपेश बघेल ने साय सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों चक्रवाती तूफान से बेमौसम हुई बारिश से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अबतक किसानों के खेत में सर्वे नहीं हो पाया है, जिससे उन्हें मुआवजा मिल सके। वहीं किसानों को फसल बीमा के बावजूद बीमा सर्वे भी नहीं हुआ और न ही बीमा का लाभ मिला। सरकार को इसपर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उपार्जन केंद्रों में एक महीने बाद किसानों का टोकन कट रहा है। किसानों के साथ ये सरकार मजाक कर रही है।

हमारे मास्टर प्लान पर सरकार ने रोक लगाया : पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि हमारे मास्टर प्लान पर सरकार ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए रोक लगा दिया। लेकिन खुद तीन साल में कुछ नहीं किया।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)